नई दिल्ली
बुधवार
02 सितंबर 2026
वर्ष: 12, अंक: 364
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

बिहार में खुलेगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का...पेज-05

DELHIN/2014/58158

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के...पेज-06

एक नजर

सरकार 35 रुपये किलो बेच रही प्याज, 19 शहरों में बढ़ाई बफर स्टॉक की सप्लाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने नासिक से 'कांदा एक्सप्रेस' के जरिए आ रहे प्याज के बफर स्टॉक को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। देश के 19 प्रमुख शहरों में 35 रुपये किलोग्राम की दर से प्याज बेचा जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और त्योहारी सीजन से पहले उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है और मौसमी कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस' और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक से प्याज को चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया गया है। प्याज की व्यापक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 30 से भी अधिक ट्रक भेजे गए हैं, जिससे 19 शहरों में खुदरा बाजार में हस्तक्षेप के प्रयास काफी बढ़ गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत रखे गए प्याज के बफर स्टॉक से आपूर्ति 24 अगस्त से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए से शुरू हुई है। इसके तहत नासिक से कांदा एक्सप्रेस की दो खेपें भेजी गई हैं। इसमें 450 मीट्रिक टन प्याज की पहली खेप 27 अगस्त को देर रात नई दिल्ली पहुंची। इसमें से 140 मीट्रिक टन प्याज वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में और बाकी बचा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वितरित किया गया। वहीं, 840 मीट्रिक टन प्याज से लदी दूसरी रेलगाड़ी 31 अगस्त को चेन्नई पहुंची।

दुनिया में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बढ़ती मांग किसानों के लिए बड़ा अवसर : शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया में प्राकृतिक खेती उत्पादों की बढ़ती मांग भारत के किसानों के लिए बड़ा अवसर है। प्राकृतिक खेती के विस्तार, किसानों की आय वृद्धि करने के लिए समग्र प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को व्यापक जन-आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा, जिससे किसानों की आय बढ़े, कृषि लागत कम हो और देश में टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। कृषि मंत्री चौहान मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान प्राकृतिक खेती से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्राकृतिक खेती के विस्तार, किसानों के पंजीकरण एवं प्रमाणन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, बाजार संपर्क, किसान उत्पादक संगठनों तथा प्राकृतिक खेती के आर्थिक प्रभावों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति, राज्यों में चल रही गतिविधियों, किसानों की भागीदारी तथा मिशन के आगामी लक्ष्यों पर प्रस्तुति दी गई। इसमें बताया गया कि वर्तमान में देशभर में 24 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 85 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

एससीओ में भारत का सुरक्षा, संपर्क, अवसर का विजन, आतंकवाद के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने पर जोर

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भारत की सोच को सुरक्षा, संपर्क और अवसर के तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित बताया और कहा कि इसके लिए आतंकवाद के समूचे तंत्र को ध्वस्त करना जरूरी है। मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में सोमवार को एससीओ शिखर सम्मेलन में विस्तार से भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने एससीओ के अगले 25 वर्षों के लिए भारत की सोच के तीन स्तंभ सुरक्षा, संपर्क और अवसर को आगे बढ़ाकर ठोस परिणामों में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसकी पहली आवश्यकता शांति और सुरक्षा है तथा आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करना होगा। उन्होंने कहा, 'इसकी पहली आवश्यकता है-शांति और सुरक्षा। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके विरुद्ध लड़ाई में हम एक्शन-रिएक्शन की सोच तक सीमित नहीं रह सकते। हमें आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती , कट्टरपंथ,और सुरक्षित ठिकानों के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। हमें एक स्वर में बोलना होगा कि इस गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मौजूदगी में जोर देकर कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती और जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं तथा आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता। मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में एससीओ ने यूरेशिया के विशाल भूभाग में संवाद और सहयोग की मजबूत परंपरा विकसित की है। अब अगले 25 वर्षों में सहयोग को स्पष्ट परिणामों में बदलना लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलकर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल कार्रवाई और प्रतिक्रिया की सोच तक सीमित नहीं रह सकती। शांत और सुरक्षित यूरेशिया की साझा आकांक्षा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता से भी जुड़ी है। भारत अफगानिस्तान के लोगों के विकास और मानवीय सहायता में योगदान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा।

उन्होंने कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता। पश्चिम एशिया के संकट का प्रभाव पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है और इसका सबसे अधिक खामियाजा वैश्विक दक्षिण के देशों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्धक्षेत्र पर नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से ही संभव है। प्रधानमंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी को केवल अपराध नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि एससीओ के तहत सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और मादक पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किए जा रहे केंद्रों को व्यावहारिक समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए। संपर्क को साझा विकास का दूसरा आधार बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि, इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक है, जो एससीओ के घोषणापत्र की मूल भावना भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सड़कों, रेलवे और हवाई गलियारों के साथ सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना और रसद नेटवर्क को अधिक दक्ष बनाना होगा। अवसर को तीसरा स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ के सहयोग का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचना चाहिए। भारत के लिए एससीओ महान सभ्यताओं, संस्कृतियों और विचारों का संगम है और अगले 25 वर्षों में लोगों के बीच संबंधों को सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता की वास्तविक कसौटी यह होगी कि युवाओं को कितने नए अवसर मिले, उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले, किसानों को प्रौद्योगिकी का कितना लाभ मिला और नागरिकों का जीवन कितना बेहतर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ में सहयोग केवल सरकार के नेतृत्व वाला नहीं, बल्कि लोगों के नेतृत्व वाला होना चाहिए। किर्गिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ में युवाओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने एससीओ में स्टार्ट-अप मंच, युवा लेखक सम्मेलन और युवा वैज्ञानिक मंच जैसी पहल की हैं।

नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द

कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च टाला

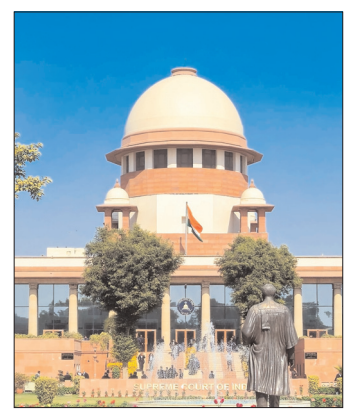

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े प्रदर्शनों के दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने और परीक्षा विवाद के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का तंत्र तीन महीने के भीतर तैयार करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय के इस निर्देश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली में आगामी पांच सितंबर को प्रस्तावित अपना मार्च वापस लेने का ऐलान कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों के समय दर्ज आपराधिक मामलों को समाप्त करने के साथ यह भी निर्देश दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन घटनाओं से संबंधित प्राथमिकियों पर आगे कार्रवाई न की जाए। इनमें ऐसे मामले शामिल नहीं है जिन्हें न्यायालय ने अपवाद माना है।

न्यायालय के फैसले के बाद सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बताया कि संगठन ने मार्च वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, 'सरकार के सकारात्मक आश्वासनों, उन्हें आज मिली न्यायिक पवित्रता और इस अदालत द्वारा पारित आदेश को देखते हुए सीजेपी पांच सितंबर के मार्च के आह्वान को वापस लेती है। गौरतलब है कि सीजेपी ने सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के आश्वासनों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश केंद्र तथा बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र द्वारा दायर उन याचिकाओं के बाद आया है जिनमें मामलों को बंद करने की मांग की गई थी। केंद्र और राज्यों ने पीठ को आश्वासन दिया कि तय विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले पहले की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार वापस लिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 20 से 26 जुलाई के बीच की घटनाओं के संबंध में कोई नयी एफआईआर दर्ज न की जाए। हालांकि, यह छूट उन अपराधों पर लागू नहीं होगी जिन्हें अदालत ने जांच के लिए विशेष रूप से अनुमति दी है। दिल्ली पुलिस को अपनी अर्जी में शामिल उन 2,873 लोगों के खिलाफ अलग से कार्रवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है जिन पर शारीरिक चोट पहुंचाने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों का सामना कर रहे लोग उचित कानूनी उपाय अपनाने के हकदार होंगे। श्री दास ने कहा कि सीजेपी का हमेशा से यह मानना रहा है कि गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों को सिर्फ़ इसलिए नहीं बचाया जाना चाहिए क्योंकि कथित अपराध विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे।

महिलाओं के लिए बहुत असुरक्षित बन गया है दिल्ली-एनसीआरः राहुल

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 45 किमी तक चलती स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म होता है लेकिन बेरोकटोक चल रही बस की कहीं कोई जांच नहीं होती। गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह घटना ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक हुई।

हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली के रिंग रोड और सीमा से गुजर गयी लेकिन उसे एक भी जांच चौकी पर नहीं रोका गया। उन्होंने लिखा कि बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है, कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं था। सवाल है कि निर्भया कांड के बाद इतने वर्षों और इतनी घटनाओं के बावजूद ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गये थे, बल्कि साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गये पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं। सवाल किया कि और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी या इस अपराध पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा।

वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर हुआ महंगा

नई दिल्ली,एजेंसी। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार से होटल, रेस्त्रां आदि में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिये हैं। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, 01 सितंबर से दिल्ली में वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 2,747.50 रुपये का मिलेगा। अगस्त में इसकी कीमत 2,738 रुपये थी। इस प्रकार कीमत 9.50 रुपये बढ़ गयी है। इससे पहले, दिल्ली में जुलाई में इसकी कीमत में 183.5 रुपये और अगस्त में 192 रुपये की कटौती की गयी थी। कोलकाता में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर आज से 11.50 रुपये और मुंबई में 9.50 रुपये महंगा हुआ है। अब इनकी कीमत क्रमश: 2,884 रुपये और 2,701 रुपये हो गयी है। चेन्नई में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10.50 रुपये बढ़ी है। अब यह 2,916.50 रुपये का हो गया है। वहीं, घरेलू उपभोग वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम सात जून के बाद से स्थिर बने हुए हैं।

गोगामेड़ी से लौट रहे यूपी के श्रद्धालुओं का वाहन पलवल में पलटा, छह की मौत, 17 घायल

पलवल,एजेंसी। कुंडली-मानेसर-पलवल मार्ग पर मंगलवार तड़के यादूपुर गांव के पास श्रद्धालुओं से भरा 22 सीटर मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। हादसे में घायल दो छोटी बच्चियों में 13 वर्षीय वाणी और आठ वर्षीय तनु भी शामिल हैं। दोनों को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी अनुसार वाहन में कुल 23 श्रद्धालु सवार थे। सभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।

श्रद्धालुओं का दल गोगामेड़ी और श्री खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहा था। इसके बाद उनकी वृंदावन और बरसाना जाने की योजना थी। मंगलवार सुबह करीब साढ़े चार बजे यादूपुर गांव के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में जान गंवाने वाले सभी छह लोगों के बीच आपस में पारिवारिक संबंध और रिश्तेदारी बताई जा रही है। मृतकों की पहचान विजय सिंह यादव पुत्र हाकिम सिंह निवासी चंदा किशनपुर, रेशमा देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी मैनपुरी, कमला देवी निवासी रामसुधु किशनपुर, राजकुमार, महेश राम सिंह निवासी मैनपुरी और सुधा पत्नी शेर सिंह के रूप में हुई है। वाहन के पलटते ही उसमें सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों का उपचार चल रहा है। सदर थाना प्रभारी हरिकिशन शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन से नियंत्रण खोने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हादसे के वास्तविक कारणों और वाहन चालक की भूमिका की जांच की जा रही है।

'सेवा संकल्प अभियान' को जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाएंः योगी आदित्यनाथ

लखनऊ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने और प्रत्येक नागरिक को 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। एक माह के इस व्यापक अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जनभागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी।

'आशीर्वाद का दीया', '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत', 'नमो सेवा गाथा', 'आंगन का उत्सव', 'कहानी बदलाव की', 'विकसित भारत संकल्प यात्रा', 'सेवा ज्योति यात्रा', 'वडनगर-सेवाराणसी यात्रा', 'सेवा मेरा योगदान', 'सेवा सेतु अभियान', 'रंगोली राष्ट्र एवं घर-घर से राष्ट्र तक', 'राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज' और 'जनसेवा महाकुंभ' इसके प्रमुख कार्यक्रम होंगे। इनके साथ प्रमुख स्मारकों पर लेजर शो, प्रमुख तीर्थस्थलों पर महायज्ञ एवं विशेष अनुष्ठान तथा ग्राम चौपाल और सीधा संवाद भी अभियान का हिस्सा होंगे। मंगलवार को अभियान की कार्ययोजना पर उच्चस्तरीय चर्चा के के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की निरंतर यात्रा है। इस अवधि में देश में हुए नीतिगत सुधारों, जनकल्याणकारी कार्यों और ऐतिहासिक बदलावों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों और प्रदेश सरकार के 10 वर्षों में हुए विकास कार्यों से आम नागरिक के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, उसकी वास्तविक तस्वीर सामने आए।

दिल्ली में 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं की छत पर बिना अग्रिम लागत के लगेगा तीन किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सौर ऊर्जा नीति का नया संस्करण (दूसरा संशोधन) पेश किया है। नई नीति के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में औसतन 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू ग्राहकों के लिए 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी शुरुआती खर्च के लगाए जाएंगे। विशेष बात यह है कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहक सोलर सिस्टम लगाने के बाद न सिर्फ सब्सिडी का फायदा पाते रहेंगे, बल्कि बचाई गई बिजली के बदले उन्हें एनर्जी-सेविंग इंसेंटिव भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' के विजन को दिल्ली में और मजबूत करते हुए सरकार ने ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिसमें आम परिवार के लिए सोलर सिस्टम लगाना आसान और लगभग बिना वित्तीय बोझ के होगा। इस नीति से दिल्ली के लोग बिजली इस्तेमाल करने के साथ-साथ बिजली भी पैदा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी-2023 (दूसरा संशोधन) के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन 'विकसित भारत' का है और विकसित भारत का रास्ता निश्चित रूप से 'विकसित दिल्ली' से होकर जाता है। इसी सोच के अनुरूप दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और सरकार का लक्ष्य केवल बिजली बिल कम करना नहीं, बल्कि दिल्ली के घरों को बिजली पैदा करने वाला घर बनाना है। प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 400 यूनिट तक की औसत मासिक बिजली खपत वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को, सोलर सिस्टम की स्थापना की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर, 3 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम बिना किसी अग्रिम लागत के उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 78,000 रुपये की सब्सिडी के साथ दिल्ली सरकार भी 78,000 रुपये की पूंजीगत सब्सिडी देगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार अतिरिक्त टॉप-अप के माध्यम से सब्सिडी और सोलर प्लांट की टेंडर में तय लागत के बीच के अंतर को भी पूरा करेगी।

दिल्ली के कचरा प्रबंधन में अब 'वेस्ट-टू-वेल्थ' पर जोर

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने और शहर को अधिक स्वच्छ एवं टिकाऊ बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय मंथन कार्यशाला का आयोजन किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय मंथन कार्यशाला: सर्कुलैरिटी की दिशा में बहु-स्तरीय/बहु-हितधारक रणनीति' का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने किया।

कार्यशाला में दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार, अपर आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा, निगम पार्षदों, आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों तथा एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि दिल्ली की अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल पारंपरिक तरीकों से संभव नहीं है। इसके लिए देश और दुनिया के सफल शहरों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें दिल्ली की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करना होगा। उन्होंने इंदौर को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और जनभागीदारी से किसी भी शहर में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने इंदौर मॉडल का गहन अध्ययन कर दिल्ली के आकार, जनसंख्या घनत्व और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसके प्रभावी पहलुओं को अपनाने पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 13,000 मीट्रिक टन नगर निगम ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऐसे में इसके वैज्ञानिक एवं टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन केवल सफाई का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और दिल्लीवासियों के जीवन की गुणवत्ता से है। उन्होंने कहा कि अब केवल कचरा उठाने और लैंडफिल तक पहुंचाने की व्यवस्था पर निर्भर रहने के बजाय कचरे को कम करने, उसके पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और संसाधन के रूप में उपयोग करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने 'वेस्ट-टू-लैंडफिल' की जगह 'वेस्ट-टू-वेल्थ' की अवधारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उपराज्यपाल ने घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे के स्रोत पर ही पृथक्करण को प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की पहली कड़ी बताया। उन्होंने गीले, सूखे, सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग-अलग रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्रोत पर उचित पृथक्करण से कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति बेहतर तरीके से की जा सकती है। साथ ही उन्होंने आधुनिक तकनीक, डिजिटल निगरानी, बेहतर डेटा प्रबंधन और उन्नत अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सक्रिय जनभागीदारी आवश्यक है। नगर निगम, जनप्रतिनिधि, आरडब्ल्यूए, बाजार संघ, उद्योग, संस्थान, विशेषज्ञ और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छता अभियान में समान हितधारक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्वच्छता को केवल नगर निगम की जिम्मेदारी मानने से स्थायी बदलाव संभव नहीं है। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली की स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है और स्वच्छ, स्वस्थ एवं बेहतर दिल्ली के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने लैंडफिल स्थलों की सफाई, स्वच्छता अवसंरचना को मजबूत करने और नई मशीनरी की तैनाती सहित एमसीडी द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। महापौर ने प्रभावी एवं सख्त प्रवर्तन व्यवस्था की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चयनित वार्डों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को प्रदर्शित करने वाले 'मॉडल वार्ड' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रयासों को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर ने लगातार और केंद्रित प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों को जवाबदेह प्रशासन, नागरिक शिकायतों के समयबद्ध समाधान और बेहतर सेवाओं के माध्यम से लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहिए। उन्होंने 'जीरो वेस्ट वार्ड', 'जीरो वेस्ट कॉलोनी' और 'जीरो वेस्ट रोड' जैसी पहलों के जरिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। एमसीडी आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और संसाधन पुनर्प्राप्ति निगम की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कचरे को स्रोत पर अलग करने से पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा मिलेगा तथा लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा कम की जा सकेगी।

दिल्ली सरकार ने बस ऑपरेटरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बस चलाने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग से जारी निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा मानक और संचालन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें दिल्ली से चलने वाली दूसरे राज्यों की बसें भी शामिल हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सुरक्षा के जरूरी नियमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। परिवहन मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बसों में लगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन हर समय चालू हालत और काम करने की स्थिति में रहें। पैनिक बटन यात्रियों की पहुंच में आसानी से होने चाहिए और हमेशा ठीक से काम करने की स्थिति में भी होने चाहिए। सभी बसों में काम करने की हालत में अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक उपचार किट का अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। बस ऑपरेटरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रात के समय या जब बसें खड़ी हों, तो उन्हें केवल अधिकृत, सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाली जगहों पर ही पार्क किया जाए। इस संबंध में कोर्ट के निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार बसों की खिड़कियों पर पर्दे या अनधिकृत फिल्में नहीं लगाई जा सकती है। बसों के विंडशील्ड, पिछली खिड़कियों और साइड की खिड़कियों के लिए तय पारदर्शिता के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इन निर्देशों में चालकों और बस स्टाफ की जिम्मेदारियों को भी साफ तौर पर बताया गया है। चालकों और दूसरे स्टाफ को यात्रियों के साथ अच्छा और विनम्र व्यवहार करना होगा। शराब या किसी भी नशे की हालत में गाड़ी चलाना सख्ती से मना है। चालकों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिफ़ॉर्म और जहां भी जरूरी हो पीएसवी बैज होने चाहिए। वहीं,

दिल्ली में 20 दिनों में 80 मोबाइल बरामद, 51 फोन मालिकों को लौटाए

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 20 दिनों के अंदर चोरी हुए 80 मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें से 51 फोन उनके मालिकों को सौंप दिए गए। शेष 29 फोन को सौंपना बाकी है। पुलिस के मुताबिक, यह अभियान 11 अगस्त से 31 अगस्त के बीच चलाया गया। मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी विश्लेषण, आधुनिक तकनीकी साधनों और फील्ड इंटेलिजेंस की मदद ली गई।

बरामदगी के बाद फोन के वास्तविक मालिकों की पहचान और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 51 फोन उनके मालिकों को वापस कर दिए गए। बरामद 80 मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा 21 फोन नॉर्थ एवेन्यू थाना क्षेत्र की टीम ने बरामद किए। इनमें से 11 फोन मालिकों को सौंप दिए गए। इसके बाद कर्तव्य पथ थाना और तुगलक रोड थाना की टीम ने 15-15 फोन बरामद किए। कर्तव्य पथ से बरामद सभी 15 में से 10 और तुगलक रोड से बरामद फोन में से छह उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। बाराखंभा रोड थाने की टीम ने 12 मोबाइल बरामद किए, जिनमें से 10 फोन वापस कर दिए गए। संसद मार्ग थाना पुलिस ने सात फोन बरामद किए और पांच मालिकों को सौंप दिए। मंदिर मार्ग थाना क्षेत्र से छह फोन बरामद हुए, जिनमें से तीन लौटाए जा चुके हैं। तिलक मार्ग थाना पुलिस ने दो फोन बरामद किए और दोनों वापस कर दिए। कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र से तीन फोन बरामद हुए, जिनमें से एक मालिक को सौंपा गया।

मुसहर समुदाय भी हमारे समाज का हिस्सा है : रामबहादुर राय

नई दिल्ली। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने मंगलवार को कहा कि मुसहर समुदाय भी हमारे समाज का हिस्सा है। रामबहादुर राय ने दिल्ली स्थित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के कलानिधि प्रभाग द्वारा 'होमस्टेड लैंड एंटाइटलमेंट एंड मुसहर कम्युनिटी इन बिहार : ए सोशल वर्क पर्सपेक्टिव' पुस्तक के लोकार्पण एवं परिचर्चा के दौरान यह बात कही। पुस्तक के लेखक डॉ. हरीश कुमार हैं और इसका प्रकाशन मानक पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में आईजीएनसीए ट्रस्ट के अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि, जबकि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

परिचर्चा में पत्रकार अरविंद मोहन तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय की डीन एवं समाज कार्य विभाग की प्रमुख प्रो. नीना पांडेय ने पैनलिस्ट के रूप में अपने विचार रखे। राय ने कहा, 'यह पुस्तक बहुत सराहनीय प्रयास है। यह पुस्तक मुसहर समुहार की जिंदगी की ओर एक खिड़की खोलती है। कारपोरेट जगत के 'सीएसआर' फंड का कुछ अंश मुसहर और कमजोर समुदायों के विकास के लिए उपलब्ध हो, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। मुसहर समुदाय भी हमारे समाज का हिस्सा है। प्रो. राणा प्रताप सिंह ने सामाजिक व्यवस्था की तुलना विज्ञान, विशेष रूप से नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स से करते हुए कहा कि मानव शरीर और उसके अंग एक जटिल प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए समाज भी एक जटिल व्यवस्था है। जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए पूरे शरीर का समग्र रूप से कार्य करना आवश्यक है, उसी प्रकार समाज के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए मुसहर समुदाय का विकास और उसका सशक्तीकरण आवश्यक है। अरविंद मोहन ने कहा कि घर मुसहर और कमजोर समुदायों के लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है, उनके जीवन का आधार होता है। उनके सम्मान और सुरक्षा का आधार होता है।

जन्माष्टमी पर उत्तर रेलवे नई दिल्ली-सूबेदारगंज और दिल्ली-हरिद्वार के बीच चलाएगा दो अतिरिक्त विशेष ट्रेनें

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और आगामी लंबे सप्ताहांत के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दो और विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। नई दिल्ली-सूबेदारगंज के बीच सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस और पुरानी दिल्ली-हरिद्वार के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। दोनों विशेष ट्रेनें तीन-तीन फेरे लगाएंगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा यात्रियों को सुगम एवं आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए इन अतिरिक्त सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

गाड़ी संख्या 02416/02415 नई दिल्ली-सूबेदारगंज-नई दिल्ली सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस 3, 4 और 5 सितंबर को नई दिल्ली से और 4, 5 तथा 6 सितंबर को सूबेदारगंज से चलेगी। इसमें वातानुकूलित, शयनयान और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे। गाड़ी संख्या 02416 नई दिल्ली से रात 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। रास्ते में यह रात 11:45 बजे गाजियाबाद, देर रात 1:05 बजे अलीगढ़, 2:18 बजे टूंडला, सुबह 4 बजे इटावा, 6:35 बजे गोविंदपुरी और सुबह 8:20 बजे फतेहपुर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02415 सूबेदारगंज से दोपहर 12:10 बजे रवाना होकर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन फतेहपुर में दोपहर 1:23 बजे, गोविंदपुरी में 2:55 बजे, इटावा में शाम 5:03 बजे, टूंडला में 6:55 बजे, अलीगढ़ में रात 8:30 बजे और गाजियाबाद में रात 10:45 बजे ठहरेगी। उत्तराखंड की तीर्थनगरी हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 04413/04414 पुरानी दिल्ली-हरिद्वार-पुरानी दिल्ली अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 3, 4 और 5 सितंबर को पुरानी दिल्ली से तथा 4, 5 और 6 सितंबर को हरिद्वार से संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04413 पुरानी दिल्ली से रात 11 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के 4:55 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। रास्ते में यह रात 11:40 बजे गाजियाबाद, देर रात 12:25 बजे मेरठ सिटी, रात 1:05 बजे मुजफ्फरनगर और तड़के 3:40 बजे रुड़की पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04414 हरिद्वार से शाम 5 बजे रवाना होकर रात 10 बजे पुरानी दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन रुड़की में शाम 6 बजे, मुजफ्फरनगर में 7:03 बजे, मेरठ सिटी में 7:55 बजे और गाजियाबाद में रात 9:08 बजे ठहरेगी।

चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप ने निर्भया कांड की यादें ताजा कीं : पुष्पा सिंह

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सिंह ने कहा कि चलती बस में 16 वर्षीय लड़की के साथ कथित गैंगरेप की जघन्य घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाने के बावजूद दिल्ली में महिला अपराधों की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही हैं।पुष्पा सिंह ने आरोप लगाया कि राजधानी में बलात्कार, छेड़छाड़, हिंसा और अपहरण सहित महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाजपा सरकार विफल रही है और दिल्ली की स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है।

उन्होंने कांग्रेस की ओर से मांग की कि चलती बस में हुई घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और पुलिस को महिला अपराधों की रोकथाम के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय करते हुए समयबद्ध कार्ययोजना लागू करनी चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में निगम में कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस महासचिव नीतू वर्मा तथा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की दिल्ली प्रभारी नीता सेहरावत ने भी अपने विचार रखे। निगम में कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को हुई घटना के 30 अगस्त को सामने आने से कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि घटना सार्वजनिक परिवहन में हुई और पीड़िता को कथित रूप से सड़क पर फेंक दिया गया, तो सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा की घटनाओं पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। नाजिया दानिश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ' जैसे नारों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके लिए जमीन पर प्रभावी व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस महासचिव नीतू वर्मा ने कहा कि राजधानी में बढ़ते महिला अपराध कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलती बस में महिला के साथ कथित रूप से लंबे समय तक यौन उत्पीड़न होना इस बात का संकेत है कि सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

सौरभ भारद्वाज के विरुद्ध मानहानि केस में परवेश वर्मा को सोशल मीडिया साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा को निर्देश दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि से संबंधित सोशल मीडिया और डिजिटल साक्ष्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

मंगलवार को परवेश वर्मा की ओर से दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर सौरभ भारद्वाज की ओर से दलीलें रखी गईं। सौरभ भारद्वाज की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने अर्जी दाखिल कर कहा कि इस मामले से जुड़े सोशल मीडिया के डाटा और डिजिटल साक्ष्य का संरक्षण जरूरी है। इस पर कोर्ट ने परवेश वर्मा को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। तब सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया कि जवाब दाखिल करने तक शिकायतकर्ता की ओर डिजिटल साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए इस पर अंतरिम आदेश दिया जाए। इसका परवेश वर्मा की ओर से पेश वकील प्रवीण कुमार ने विरोध करते हुए कहा कि अगर आज भी आदेश चाहिए था तो याचिका की प्रति अग्रिम रुप से दी जानी चाहिए थी। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि सभी डिजिटल साक्ष्य शिकायतकर्ता के कब्जे में है इसलिए उनके संरक्षण का अंतरिम आदेश जारी किया जाता है। कोर्ट ने मेटा और एक्स को भी सही डिजिटल साक्ष्य संरक्षित रखने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट ने 8 अगस्त को सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया था। परवेश वर्मा ने 4 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था। परवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया।

जन्माष्टमी पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, मथुरा, वाराणसी और रींगस के लिए मिलेंगी अतिरिक्त सेवाएं

नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने मथुरा, वाराणसी और रींगस के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन विशेष सेवाओं के जरिए जन्माष्टमी के दौरान प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने मंगलवार को बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और उनकी सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें मथुरा के लिए दो जोड़ी अनारक्षित विशेष ट्रेनें, दिल्ली-वाराणसी के बीच विशेष एक्सप्रेस और दिल्ली-रींगस के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन शामिल हैं।

उत्तर रेलवे के अनुसार, हजरत निजामुद्दीन और मथुरा जंक्शन के बीच गाड़ी संख्या 04410/04409 अनारक्षित विशेष ट्रेन 3, 4 और 5 सितंबर को दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी। हजरत निजामुद्दीन से यह ट्रेन सुबह 10:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:05 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी में मथुरा से दोपहर 1:35 बजे चलकर शाम 4:45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04412/04411 हजरत निजामुद्दीन-मथुरा-हजरत निजामुद्दीन अनारक्षित विशेष ट्रेन भी 3, 4 और 5 सितंबर को दोनों दिशाओं में तीन-तीन फेरे लगाएगी। यह ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से सुबह 9:45 बजे रवाना होकर दोपहर 12:20 बजे मथुरा पहुंचेगी। वापसी में मथुरा से दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर शाम 4:30 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। मथुरा जाने वाली दोनों विशेष ट्रेनें ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसी कलां, छाता, अझई, वृंदावन रोड और भूतेश्वर सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहरेंगी। इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से मथुरा जाने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 04446/04445 दिल्ली-वाराणसी-दिल्ली विशेष एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। इसमें वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे लगाए जाएंगे।

स्थायी समिति की बैठक में जनहित के कई मुद्दों पर मंथन, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें राजधानी के नागरिकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम, स्वाइन फ्लू, अवैध प्ले स्कूल, अवैध खाने के ठेले, खुले में तंदूर का इस्तेमाल, अतिक्रमण, बेसहारा पशु, पार्कों के रखरखाव, प्रदूषण और स्वच्छता व्यवस्था जैसे विषय प्रमुखता से उठाए गए। बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति लोकतांत्रिक संवाद और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। बैठक में पक्ष एवं विपक्ष के सभी पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया। सत्या शर्मा ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराने तथा जनजागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए नागरिकों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। इस अभियान में संबंधित क्षेत्र के पार्षदों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों तक बचाव संबंधी जानकारी पहुंचाई जा सके। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर भी स्थायी समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वाइन फ्लू से बचाव, सावधानियों और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा, ताकि नागरिक समय रहते आवश्यक सावधानी बरत सकें। स्थायी समिति की बैठक में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे प्ले स्कूलों का मुद्दा भी उठाया गया। सत्या शर्मा ने अधिकारियों को ऐसे संस्थानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। प्ले स्कूलों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से संचालित खाने के ठेलों तथा खुले में तंदूर के इस्तेमाल को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। स्थायी समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों को ऐसे स्थानों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों और यातायात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जाए।

बैठक में दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे आवारा एवं बेसहारा पशुओं की समस्या को भी गंभीरता से उठाया गया। सत्या शर्मा ने कहा कि सड़कों पर पशुओं की मौजूदगी से यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर नई गौशालाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा। इससे सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति का उद्देश्य केवल प्रस्ताव पारित करना नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने

एक नजर

एप्पल कस्टमर सर्विस के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी के 11 आरोपी काबू

गुरुग्राम,एजेंसी। फर्जी एप्पल कस्टमर सर्विस बनकर अमेरिका के नागरिकों से करोड़ों की ठगी कर ली गई। इस तरह से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मंगलवार को पालम विहार से 11 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस थाना साइबर अपराध पश्चिम को सूचना मिली थी कि प्लॉट नंबर-1208, जे-ब्लॉक पालम विहार में बिना अनुमति फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। सूचना पर एक सितंबर को रेड की गई। मौके पर आरोपी लैपटॉप, हेडफोन/माइक और मोबाइल फोन पर एक्स लाइट डायलर और एपल फेस टाइम के जरिए अंग्रेजी में विदेशी नागरिकों से बात करते मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रितपाल सिंह (सुभाष नगर, दिल्ली), मोहम्मद रिजान अंसारी (सदर बाजार, दिल्ली), चैतन्य गोयल (सेंट्रल दिल्ली), मनीष (भद्रक, ओडिशा), शाहरुख अंसारी (सदर बाजार), संजीव पांडे (आजादपुर), शिवम (वजीराबाद), आदित्य (उत्तम नगर), दीपक त्रिवेदी (उत्तम नगर), वरुण गौतम (उत्तम नगर) और नीरज (रोहतक, हरियाणा) के रूप में हुई। थाना साइबर अपराध पश्चिम में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में पता चला कि प्रितपाल सिंह कॉल सेंटर का टीम लीडर था। आरोपी करीब तीन महीने से मकान किराए पर लेकर कॉल सेंटर चला रहे थे। सभी कॉलर कमीशन पर रखे गए थे। मुख्य संचालक एक अन्य व्यक्ति है। आरोपी अमेरिकी नागरिकों को मोबाइल में वायरस/तकनीकी समस्या का झांसा देकर वर्चुअल टोल फ्री नंबर पर कॉल करवाते थे। खुद को एप्पल का कर्मचारी बताकर उनकी समस्या सुलझाने के नाम पर फेडरल ट्रेड कमीशन का फर्जी पत्र दिखाकर डराते थे और 10,000 से 20,000 डॉलर की ठगी करते थे। रकम विदेशी बैंक खाते में ट्रांसफर करवाते और गिफ्ट वाउचर/कार्ड के नंबर भी ले लेते थे। पुलिस ने मौके से नौ लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, दो हेडफोन/माइक, दो कार, एक बाइक और एक स्कूटी बरामद की है।

नूंह में 14 सितंबर तक चलेगा कुष्ठ रोगी पहचान अभियान

नूंह,एजेंसी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के नूंह और पुन्हाना क्षेत्र में 1 से 14 सितंबर तक कुष्ठ रोगी पहचान अभियान एवं शहरी कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाएगा। अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं और पुरुष स्वयंसेवकों की टीमें घर-घर जाकर कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की पहचान करेंगी। इसके बाद संदिग्ध मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना ने मंगलवार को बताया कि कुष्ठ रोग से घबराने की जरूरत नहीं है। यह जीवाणु जनित रोग है, जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। समय पर बीमारी की पहचान और पूरा उपचार मिलने पर मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। उपचार में देरी होने पर स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ सकता है।

उन्होंने बताया कि त्वचा पर सफेद या तांबे जैसे रंग के धब्बे, धब्बे वाले स्थान पर संवेदना कम होना या खत्म होना, पसीना और बाल कम होना कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा हाथ-पैर में सुन्नपन, झनझनाहट या कमजोरी तथा हाथ, पैर, आंख या चेहरे पर सूजन अथवा गांठ भी बीमारी के संभावित संकेत हो सकते हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर बीमारी को छिपाने के बजाय तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग की जांच और उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध है। मरीजों का उपचार बहु-दवा चिकित्सा पद्धति से किया जाता है। उन्होंने जिला वासियों से अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों का सहयोग करने की अपील की। साथ ही परिवार और आसपास के लोगों में कुष्ठ रोग के संभावित लक्षण दिखाई देने पर उन्हें जांच के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और नियमित उपचार से बीमारी के साथ-साथ इससे होने वाली विकलांगता को भी रोका जा सकता है।

फरीदाबाद पुलिस ने 11 लाख के 38 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद

फरीदाबाद। एनआईटी जोन की साइबर सेल ने तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए 11 लाख रुपये से अधिक कीमत के 38 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने में सफलता हासिल की है। बरामद किए गए मोबाइल फोन मंगलवार को डीसीपी एनआईटी उत्तम द्वारा अपने कार्यालय में उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द किये गए। लंबे समय से अपने गुम हुए मोबाइल फोन के मिलने की उम्मीद छोड़ चुके लोगों के लिए यह खुशी का अवसर रहा। मोबाइल फोन प्राप्त करने वाले नागरिकों ने फरीदाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश के लिए एनआईटी जॉन की साइबर सेल द्वारा केंद्र सरकार के सीईआरआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का तकनीकी विश्लेषण किया गया। टीम ने मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर, डिजिटल ट्रैकिंग, नेटवर्क संबंधी तकनीकी जानकारी एवं अन्य आधुनिक संसाधनों की सहायता से फोन की पहचान की। विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फोन की लोकेशन एवं उपयोग संबंधी जानकारी मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया गया है।

शराब के नशे में रील देखते हुए चला रहा था ट्राला, यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में 4 की मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार

जेवर,एजेंसी। यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार को चार लोगों की जान लेने वाले भीषण हादसे की पुलिस जांच में चालक की घोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस पूछताछ के अनुसार आरोपित चालक शराब के नशे में मोबाइल पर रील देखते हुए ट्राला चला रहा था। साबौता कट के पास उसने अचानक तेज रफ्तार में ट्राला दाईं ओर मोड़ दिया। नियंत्रण बिगड़ने पर ट्राला एक्सप्रेसवे के बीच लगे दो क्रैश बीम बैरियर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में पहुंच गया और सामने से आ रहे तीन वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद चालक मौके से ट्राला लेकर भागने लगा। लोगों ने पीछा किया तो उसने 315 बोर का तमंचा लहराकर गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने घेराबंदी कर

आरोपित को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। आगरा के बाह थाना क्षेत्र के झाड़े की गढ़ी निवासी बाइक सवार सुमित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार आरोपित दिनेश चंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी लोरियापट्टी, थाना मंगरौली, जनपद मथुरा से पूछताछ में पता चला कि वह 30 अगस्त को ट्राला लेकर नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था। ट्राला से डस्ट खाली करने के बाद उसने शराब का सेवन किया। इसके बाद नशे की हालत में ही वाहन चलाने लगा। इस दौरान उसका ध्यान सड़क पर कम और मोबाइल पर रील देखने में अधिक था। साबौता इंटरचेंज के पास पहुंचने पर चालक को इंटरचेंज और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच बना डिवाइडर दिखाई दिया। उसने ट्राला को अचानक दाईं ओर मोड़ दिया। तेज रफ्तार होने के कारण वह वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका। ट्राला डिवाइडर के दोनों तरफ लगे क्रैश बीम बैरियर को तोड़ते हुए आगरा से मथुरा की ओर जाने वाली लेन में पहुंच गया। गलत दिशा में पहुंचने के बाद ट्राला ने सामने आ रहे वाहनों को रौंद दिया। हादसे में महाराजगंज के मूल निवासी विकास गुप्ता, दिल्ली के नजफगढ़ निवासी अधिवक्ता रितेश कुमार पांडेय, उनके पुत्र अभिसार पांडेय और राजस्थान के धौलपुर निवासी चालक विजय सिंह की मौत हो गई। बाइक सवार सुमित और सचिन तथा छोटा हाथी चालक बिहार के सिवान के रामपुर निवासी भूषण गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर करीब पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस अब हादसे में सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

फरीदाबाद में बच्ची समेत नहर में कूदी महिला, तलाश में जुटी टीमें

फरीदाबाद। सेक्टर-56 क्षेत्र से गुजर रही गुरुग्राम कैनाल नहर में एक महिला और उसकी छोटी बच्ची के कूदने की सूचना के बाद सेक्टर-55 पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब चार घंटे तक पुलिस टीम ने लगातार नहर और आसपास के क्षेत्र में तलाश की, लेकिन अभी तक महिला या बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। सेक्टर-55 चौकी इंचार्ज देवदूत ने बताया कि, मंगलवार सुबह एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक महिला अपने बच्चे के साथ नहर में कूद गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पुलिस ने राहगीर की सूचना को आधार बनाकर नहर में तलाश शुरू की। टीम ने कई घंटे तक लगातार नहर में संभावित स्थानों पर सर्च किया, लेकिन अभी तक किसी के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, ताकि नहर में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा सके। पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि घटना को लेकर लोगों की ओर से अलग-अलग जानकारी दी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ नहर में कूदी है, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि महिला, बच्ची और एक पुरुष तीनों नहर में कूदे हैं।

संक्रामक रोगों का हॉटस्पॉट बना मेरठ मंडल, स्वाइन फ्लू-डेंगू के 435 मामले आए सामने

गाजियाबाद। शासन स्तर से आये दिन जारी होने वाले दिशा निर्देशों के बाद भी एक जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक संचालित होने वाला डोर टू डोर संचारी रोग नियंत्रण अभियान बेअसर हो रहा है। कम से कम मेरठ मंडल के छह जिलों की ताजा रिपोर्ट से तो यह साफ लगता है। 31 अगस्त देर शाम को जारी की गई रिपोर्ट बयां कर रही है कि मेरठ मंडल संक्रामक रोगों का हाट स्पाट बनता जा रहा है। मेरठ मंडल में स्वाइन फ्लू के संग डेंगू ने भी पैर पसारने शुरू कर दिये हैं।अगस्त तक मंडल के छह जिलों में स्वाइन फ्लू के 302 और डेंगू के 133 केस मिल चुके हैं। मलेरिया के 83,स्क्रब टायफस के 25,लेप्टोस्पायरोसिस के 27 और चिकनगुनिया का भी एक केस मिल चुका है। खास बात यह है कि शासन स्तर से रोज समीक्षा होने के बाद भी संचारी रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सर्वे भी कमजोर पड़ रहा है। अधिकांश केस प्राइवेट लैबों में जांच के बाद पुष्ट किये जा रहे हैं। जिले वार गठित सर्विलांस विंग और मलेरिया अनुभाग की गतिविधियां भी संचारी रोग बढने पर सवालों के दायरे में आ रहीं हैं। हर साल सर्वे एवं एंटी लार्वा स्प्रे और लार्वा नष्ट करने के लिये ब्रीड चेकर रखे जाते हैं। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया जाता है।

नोएडा वासियों को ट्रैफिक के शोर से मिलेगी राहत

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। अगाहपुर से एनएसईजेड सेक्टर-82 तक बने 5.5 किलोमीटर लंबे भंगेल एलिवेटेड रोड पर नॉइज बैरियर लगाया जाएगा। इसके लिए जारी किए गए टेंडर में पांच कंपनियों ने भाग लिया है, जिनके दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। चयनित कंपनी के काम का अवार्ड होते ही नॉइज बैरियर लगाने का कार्य प्रारंभ होगा। इससे एलिवेटेड रोड के दोनों तरफ लाखों लोगों को लाभ होगा।

नॉइज बैरियर के लिए 18.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह एलिवेटेड रोड अगाहपुर, सेक्टर-40, 49, 48, 107 बरौला और भंगेल गांव की आबादी के बीच से गुजरता है। ट्रैफिक के शोर से प्रभावित आसपास के सेक्टर और गांव के निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने यह योजना बनाई है। प्राधिकरण एक एजेंसी का चयन करेगा, जिसे यह कार्य पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। साउंड बैरियर की ऊंचाई छह फीट होगी, और इसके निर्माण के मानक इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) से लिए गए हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता 80 डेसिबल होती है, इससे अधिक की आवाज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 0 से 25 डेसिबल तक की आवाज शांत वातावरण को दर्शाती है, जबकि 80 डेसिबल से अधिक की आवाज से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण वर्क सर्किल

आठ वरिष्ठ प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि नॉइज बैरियर हाईवे और आवासों के बीच एक ध्वनि अवरोधक के रूप में कार्य करेगा, जो ध्वनि को समाप्त नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रभाव को कम करेगा। यह 50 डेसिबल तक ध्वनि को कम करने की क्षमता रखता है, जिससे घरों तक पहुंचने वाला ध्वनि प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा। एलिवेटेड रोड के दोनों ओर नॉइज बैरियर लगने के बाद सेक्टर-42, 48, 49, 47, 110, 107 के निवासियों को कोई परेशानी नहीं होगी।

महिला थाना एवं परामर्श केंद्र की पहल से बिखरे 41 परिवारों में लौटी खुशियां

बागपत,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में महिला थाना एवं महिला परामर्श केंद्र की कर्मचारियों के सहयोग से पारिवारिक विवादों के समाधान निस्तारण किया गया। इस वजह से एक बार फिर 41 परिवारों में खुशियां लौटी है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार ने इसको सामाजिक परिवेश में पुलिस की महत्वपूर्ण भागेदारी बताया है। पुलिस अधीक्षक कार्यायल से मंगलवार को जारी सूचना में बताया कि अगस्त-2026 के दौरान प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए विस्तृत काउंसलिंग की गई। इस दौरान पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर संवाद स्थापित कराया गया। काउंसलरों ने सभी की बातों को सुनकर उन्हें समझाया और उनके आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिससे कई टूटते परिवार पुन: एक साथ आने को तैयार हुए।

सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप कुल 41 पारिवारिक विवादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

समझौता प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी परिवारों को आपसी सहमति से पुन: एकजुट किया गया और उनके उज्ज्वल, सुखद एवं शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करते हुए रवाना किया गया। बता दें कि महिला थाना एवं परामर्श केंद्रों पर समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने, वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने तथा विवादों को न्यायालय से पूर्व सुलझाने के लिए पुलिस विभाग का यह कदम परिवारों में खुशियां लौटा रहा है।

ग्रेनो वेस्ट को दिसंबर तक मिलेगा दूसरा एसटीपी

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 45 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका 90 फीसदी सिविल कार्य पूरा हो चुका है और 60 फीसदी मशीनें भी लग चुकी हैं। इसके चालू होने से क्षेत्र में सड़कों पर गंदा पानी बहने की समस्या खत्म होगी। यह ग्रेटर नोएडा वेस्ट का दूसरा एसटीपी होगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित इस एसटीपी पर 80 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। निर्माण, संयंत्र और बिजली का काम पूरा कर नवंबर-दिसंबर में इसे शुरू करने का लक्ष्य है। कार्यदायी संस्था को 10 साल तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही 80 एमएलडी क्षमता के एक और एसटीपी की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नालेज पार्क-5 में जगह चयनित की गई है और इसकी डीपीआर की जांच आइआइटी से कराई जा रही है। इसके अलावा नालेज पार्क-5 में 50 एमएलडी और आइटी सिटी में 12 एमएलडी क्षमता के एसटीपी की भी योजना है।

बिल विवाद में मेदांता ने शव रोका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चेतावनी के बाद परिजनों सौंपा

गुरुग्राम। मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी 30 वर्षीय युवक की मौत के बाद बिल विवाद का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि 23 लाख रुपए लेने के बाद भी अस्पताल 18 लाख और मांग रहा था और शव नहीं दे रहा था। मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने और आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की सख्त पोस्ट के बाद अस्पताल ने बिना बकाया लिए शव परिजनों को सौंप दिया।

परिजनों के मुताबिक युवक को गंभीर हालत में मेदांता में भर्ती कराया गया था। जमा-पूंजी और उधार लेकर उन्होंने 23 लाख रुपए अस्पताल को दिए, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल ने 18 लाख रुपए का अतिरिक्त बिल बताया। परिजनों ने इतनी बड़ी राशि तुरंत देने में असमर्थता जताई और शव सौंपने की गुहार लगाई। मामला एनएचआरएस तक पहुंचा। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा-गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शाहजहांपुर निवासी 30 वर्षीय युवक की मृत्यु के बाद उसका शव परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा है। परिजन 23 लाख भर चुके हैं, अभी 18 लाख और मांगा जा रहा है। अस्पताल न तो प्रशासन की बात मान रहा है, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और न एनएचआरसी की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। अब इस अस्पताल का इलाज करने मैं स्वयं जा रहा हूं। अध्यक्ष की चेतावनी के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा और बिना शर्त शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव मिलने के बाद परिजन शाहजहांपुर के लिए रवाना हो गए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवक को किस बीमारी के चलते भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी की गाइडलाइन कहती है कि बिल बकाया होने पर शव को बंधक नहीं बनाया जा सकता। यह मानवाधिकार और मृतक की गरिमा का उल्लंघन है।

गुरुग्राम के डीटीपी को सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना, अनुशासन की ट्रेनिंग देने की सिफारिश

गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर में कब्जे तोड़ने को लेकर खौफ का पर्याय बने नगर निगम के डीटीपी एवं नोडल अधिकारी आरएस बाठ पर सूचना आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग की ओर से डीटीपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगया गया है। उन पर आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी देने में लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय सुरा की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सिफारिश की है कि आरएस बाठ को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में भेजकर कर्तव्य निर्वहन और कानून की विशेष ट्रेनिंग दिलाई जाए।

आयोग ने कहा कि उन्हें कानून और अनुशासन सिखाने की जरूरत है। मामला चार जनवरी 2022 की एक आरटीआई का है। आरटीआई कार्यकर्ता भारत जैन ने नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग से 2007 से 2016 के बीच स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आंशिक कब्जा सर्टिफिकेट जारी करने के नियमों की बिंदु अनुसार जानकारी मांगी थी। आयोग ने 13 जुलाई 2023 को ही दो सप्ताह में जानकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग की ओर से देरी की जाती रही। आरएस बाठ ने आयोग में दलील दी कि संबंधित नियम, नीतियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और आवेदक को रिकॉर्ड निरीक्षण का मौका भी दिया गया था। आयोग ने तर्क खारिज करते हुए कहा कि यदि नागरिक ने विशिष्ट जानकारी मांगी है और वह विभाग के पास उपलब्ध है, तो जनसूचना अधिकारी को प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट जवाब देना होगा। केवल वेबसाइट का हवाला देकर जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। सुनवाई में यह पता चला कि डीटीपी आरएस बाठ को कई अवसर दिए गए, लेकिन वे बार-बार सुनवाई से नदारद रहे। 30 जुलाई 2026 के आदेश के बाद भी निदेशक को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देने पड़े। आयुक्त ने कहा कि वैधानिक प्राधिकरण के निर्देश सलाह नहीं होते, उनका पालन करना सरकारी पद का अनिवार्य दायित्व है। जुर्माना राशि तीन महीने में वसूलनी होगी। ट्रेनिंग में कानून के अनुसार ड्यूटी, वैधानिक अथॉरिटी के निर्देशों का पालन, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और जवाबदेही जैसे विषय शामिल करने को कहा गया है।

गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी, राजनगर एक्सटेंशन से वैशाली और मेरठ रोड तक चलेंगी ई-बसें

गाजियाबाद,एजेंसी। राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए अब वहां से वैशाली और मेरठ रोड के लिए ई-बसों का संचालन किया जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को कलक्ट्रेट में हुई व्यापार बंधु की बैठक में ई-बस संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जल्द जिले को 50 नई ई-बसें मिलेंगी, जिनमें से कुछ बसें राजनगर एक्सटेंशन से इन दोनों रूटों पर चलाई जाएंगी।

डीएम ने कहा कि नई ई-बसों के संचालन से राजनगर एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में व्यापारियों और वाहन चालकों की सुविधा से जुड़े मुद्दों पर भी निर्देश दिए गए। डीएम ने मोहन नगर चेक पोस्ट पर मोबाइल शौचालय स्थापित करने के लिए कहा। खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट छह से आठ माह तक नहीं मिलने के मामले में एडीएम सिटी को एक माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए

गए, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके। डीएम ने नगर निगम के अधिकारियों को अवैध बस स्टैंड और सड़क किनारे खड़े होने वाले कबाड़ वाहनों के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा हापुड़ रोड और कचहरी मार्ग की मरम्मत का काम जल्द कराने के लिए कहा गया, ताकि वाहन चालकों को आवागमन में होने वाली परेशानी दूर हो सके। बैठक में डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में तिलक राज अरोड़ा, पं. अशोक भारतीय, केसरी कुमार मिश्र, प्रशांत सरैया, पंकज गर्ग, अवधेश शर्मा सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद रहे।

पंजाब में चुनावी वादों के बीच भरोसा तलाशते मतदाता

ज्योति मल्होत्रा

पिछले सप्ताहांत से पंजाब में सिर्फ़ मौसम ही नहीं बदल रहा है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, जो राज्य और देश के बाकी हिस्सों का पेट भरने वाली ज़मीन को सींचता है, हर साल की तरह समाप्ति पर है। इसके साथ ही हिंदू कैलेंडर का 'सावन' माह भी बीत गया। इसलिए, कल रात जब 'सावन' की आखिरी पूर्णिमा-यानी 'रक्खड़ पुन्या' या रक्षाबंधन-पर पूरा चांद निकला, तो उसकी चांदी सी चमक में आने वाले मौसम का राज़ भी छिपा था : कुछ ही महीनों बाद, सर्दियों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब का ताज़ किसके सिर सजेगा? ऐतिहासिक बाबा बकाला गुरुद्वारे में-जहां 1664 में नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर की पहचान उजागर हुई थी- 'रक्खड़ पुन्या' के मौके पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई। इस दिन पारंपरिक रूप से होने वाली रैलियों में सभी सियासी दलों ने ताकत दिखाई। पहली बार बीजेपी ने भी रैली की, जिससे संकेत मिला कि वह पंजाब में फिर वापसी करना चाहती है- चाहे अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से मिलकर या अकेले। चुनाव में छह महीने बचे हैं और 'इंडिया टुडे' ग्रुप के 'मूड ऑफ़ द नेशन' पोल ने उल्टी गिनती को और तेज़ कर दिया है। इस पोल से पता चलता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राष्ट्रीय वोट शेयर में 45.1 फीसदी के साथ काफी आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 39.1 प्रतिशत है-ज़ाहिर है, यहां प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन बारीकी से राजनीति पर नज़र रखने वाले लोग देखेंगे कि एनडीए का वोट शेयर इस जनवरी में अनुमानित 47 प्रतिशत से 2 फीसदी कम हो गया है और यह एक साल पहले रहे 46.7 प्रतिशत से भी कम है।

तो अगले साल की शुरुआत में पंजाब के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले चुनावों के लिए इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों से चली आ रही अपनी जीत की लय को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है - तब से उसने कई राज्यों में शानदार जीत हासिल की है, चाहे वह हरियाणा हो, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार हो या पश्चिम बंगाल। अब बीजेपी पंजाब जीतना चाहती है। उसे मालूम है कि वह उत्तर प्रदेश जीत सकती है, भले ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना हो; मणिपुर में भी जीत सकती है, भले ही वहां तीन साल से जातीय संघर्ष चल रहा है व अभी तक सुलझा नहीं; गोवा में भी, जहां वह लगातार तीन बार जीत चुकी। बंगाल जीतने के बाद, अब बीजेपी की महत्वाकांक्षा देश के दूसरे छोर तक फैल गई। इसीलिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील करने बाबा बकाला गए और कहा, हमें वोट दें, हम आपकी समस्याएं हल करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई लोग पंजाब को कुछ समय से यही संदेश दे रहे हैं। हम आपका कर्ज़ माफ़ करेंगे, सीमा पार से ड्रोन के ज़रिए आने वाले नशों को रोकेंगे, खेती को बेहतर बनाएंगे, स्कूल ठीक करेंगे, सड़कें बनाएंगे और हरियाणा व राजस्थान के साथ पानी के बंटवारे का मुद्दा सुलझाएंगे। अनकहा संदेश? बीजेपी को वोट दें। बेशक, पंजाब में कुछ खास बात है। यहां के लोग असाधारण दरियादिली दिखाते हैं- जैसे दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए गुरुद्वारों का खुलना और हाल के हफ़्तों में असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाबियों का जाना- ऐसी दरियादिली देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं दिखती। इसकी सीमा एक मुश्किल पड़ोसी से लगती है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि बीजेपी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से क्यों नहीं खोल रही। बंगाल के उलट - आज़ादी के बाद उसका रिश्ता भी आजादी के बाद के 80 सालों में ज़्यादातर समय दिल्ली के साथ कांटे का रहा है, सिवाय पिछले कुछ महीनों के- पंजाब को दो बार बांटा गया- हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के रूप में - और आतंकवाद, उद्योगों के पलायन और हरित क्रांति के विपरीत प्रभाव ने इसकी अपनी छवि को और कमज़ोर किया है। पंजाबियों का एक शब्द है, जिसे वे कई स्थितियों के लिए काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह उनके वजूद की सबसे गहरी भावना से जुड़ा है - वह शब्द है 'धक्का', मतलब- 'मुझसे ज़बरदस्ती मत करो'। मसलन, 'मेरे तों धक्के नाल कम ना कराओ। यानी, मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए मजबूर न करें'। यह एक ऐसा वाक्यांश है जिसे पंजाब को जीतने की चाह रखने वाले हर राजनीतिक दल को याद रखना चाहिए और अपने अंदरूनी दस्तावेज़ों में इसे एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी का बिना मांगा सबक यह है कि पंजाब के 2.1 करोड़ वोटरों को - जो अब 1.9 करोड़ रह गए हैं, क्योंकि गहन मतदाता पुनरीक्षण की छलनी से गुज़रने के बाद लगभग 20 लाख वोटर छंट चुके हैं - धर्म (सिख, हिंदू), जाति (जाट, खत्री, रविदासिया, रामदासिया, वाल्मीकि आदि), डेरों (राधा स्वामी, सचखंड बल्लां, सच्चा सौदा आदि), धर्मगुरुओं (संत निरंजन दास, राम रहीम) के आधार पर बांटकर आप मान लें कि इनके वोटों को इकट्ठा कर सकेंगे। जिस राज्य को आप जीतना चाहते हैं, उसे बदनाम न करें, यह कहकर कि स्कूलों की हालत खराब हैं, कॉलेज का हाल और भी बुरा है, बुड्ढा दरिया एक गंदा नाला भर है, उद्योग बेपरवाह होकर दूषित पानी इसमें डाल रहे, गुंडागर्दी और नशे का बोलबाला है- भले ही इनमें से अधिकांश सच हों। अगर आप राज्य जीतना चाहते हैं, तो उसे बेहतर बनाने में मदद करें। स्पष्टत: राज्य को आपकी मदद की ज़रूरत है। अब जबकि पंजाब में चुनाव से पहले के आखिरी छह महीने के दौर में दाखिल हो चुका है, और यह निरंतर साफ़ होता जा रहा है कि न तो भाजपा और न ही शिरोमणि अकाली दल अकेले दम जीत हासिल करने को ज़रूरी जोश पैदा कर पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री को अहसास है कि इस अनोखे हालात पर नज़र रखने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने गुजरात से अपने करीबी सहयोगी, नवसारी से चार बार के सांसद और गुजरात में भाजपा के पहले गैर-गुजराती प्रदेशाध्यक्ष, वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी है। दोनों पुराने सहयोगियों के बीच गठबंधन की संभावना इसलिए है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, न कि इसलिए कि वे ऐसा करना चाहते हैं।

यह मुकाबला लगातार काफ़ी अनोखा होता जा रहा है। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सब्सिडी वाली योजना से सीख ली है - जैसा कि भाजपा ने देश के दूसरे हिस्सों (हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली) में महिलाओं के बैंक खातों में पैसे डालकर कामयाबी हासिल की थी, वैसा ही आप इस राज्य में कर रही है। कांग्रेस, जो शायद अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, उसे तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी यह तय नहीं कर पा रहे कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा- अगले हफ़्ते राज्य का उनका दौरा पार्टी में चल रही गुटबाज़ी पर आखिरी मुहर लगा देगा। इस बीच, जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के संगठन 'वारिस पंजाब दे' और उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। मतदान से पहले के, अगले छह महीने बहुत अहम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब के लोग राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों का आकलन इस आधार पर नहीं करेंगे कि वे किस रंग की पगड़ी पहनते हैं - या पड़ोसी राज्यों से आने वाले नेता इसे कभी-कभार क्यों पहनते हैं - बल्कि इस आधार पर करेंगे कि रैलियों, भाषणों और नुक्कड़ सभाओं में वे जो कहते हैं, क्या सच में वही उनका मंतव्य भी है। जॉन एफ. कैनेडी की मशहूर उक्ति को कुछ हेरफेर से कहें तो : 'यह मत पूछिए कि पंजाब आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह कि आप अपने प्यारे राज्य के लिए क्या कर सकते हैं।

बच्चों में आई फोन की इस बढ़ती चाहत के पीछे सोशल मीडिया, दोस्तों के समूह का प्रभाव और विज्ञापनों की बड़ी भूमिका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर महंगे फोन को सफलता , सम्पन्नता और आधुनिक जीवनशैली से जोड़कर दिखाया जाता है। जब एक बच्चा अपने दोस्तों के हाथ में नया आई फोन देखता हैं तो उसके मन में भी वैसा ही फोन पाने की ललक पैदा होती है। कई बार यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हैं।वह चोरी, डकैती या कोई भी अपराध करने को भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार जिद और सामाजिक दबाव में वह अपना विवेक खोकर किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। इस प्रवृत्ति का असर केवल परिवार के बजट पर नहीं, बल्कि बच्चों की सोच पर भी पड़ता है। यदि बच्चा अपनी पहचान को सिर्फ महंगे फोन और ब्रांडेड वस्तुओं से जोड़ने लगे, तो उसमें दिखावे और तुलना की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये हम सभी जानते है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से पढ़ाई, नींद, एकाग्रता प्रभावित होती है। इसका समाधान बच्चों को पूरी तरह तकनीक से दूर करना नहीं है, क्योंकि ऐसा कर पाना मुश्किल है । स्मार्टफोन आज शिक्षा, संपर्क और जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। जरूरत है कि माता-पिता, शिक्षक बच्चों को तकनीक और उपभोक्तावाद के बीच अंतर समझाएं। फोन खरीदते समय उसकी कीमत या ब्रांड के बजाय उसकी उपयोगिता, जरूरत और परिवार की आर्थिक क्षमता को देखे।

बच्चों में आई फोन का बढ़ता एडिक्शन

प्रो. मनीषा शर्मा

आज के डिजिटल क्रांति के युग में मोबाइल फोन बच्चों की दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, मनोरंजन और लोगो से संपर्क के लिए इसका प्रचलन इस कदर बढ़ गया है कि इसके बिना जीने की कल्पना मात्र से युवा सिहर जाते है। इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन आज युवाओं के मध्य महंगे और ब्रांडेड फोन, खासकर आई फोन को लेकर बढ़ती दीवानगी माता-पिता के लिए चिंता का सबब बन रही है। कई बच्चे फोन को अपनी जरूरत से ज्यादा स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। इसी एडिक्शन का शिकार हुआ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर (औसा)का कुणाल, जिसने आई फोन की जिद में अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया । ना सिर्फ अपने बल्कि अपने मां-बाप की जिंदगी को भी अपनी जिद की भेंट चढ़ा दिया। कुणाल जो 19 वर्ष का था अपनी आई फोन खरीदने की जिद के कारण पहाड़ी से कूद कर जान देने की कोशिश करने लगा उसको बचाने में पिता गिर गए और इस सदमे में उसकी मां भी पहाड़ी से कूद गई। खबरों से पता चला कि उसने आई फोन खरीद लिया था पर ईएमआई भरना उसके बस की बात नहीं थी। उसने परिवार से जिद की, परिवार वालों ने समझाया कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वह ईएमआई भर पाए । बस वह अपनी जिद पूरी करने और घरवालों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पहाड़ी पर चला गया और कहने लगा कि नहीं भरोगे तो नीचे कूद जाऊंगा। इसी घटनाक्रम में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है।

बच्चों में आई फोन की इस बढ़ती चाहत के पीछे सोशल मीडिया, दोस्तों के समूह का प्रभाव और विज्ञापनों की बड़ी भूमिका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर महंगे फोन को सफलता , सम्पन्नता और आधुनिक जीवनशैली से जोड़कर दिखाया जाता है। जब एक बच्चा अपने दोस्तों के हाथ में नया आई फोन देखता हैं तो उसके मन में भी वैसा ही फोन पाने की ललक पैदा होती है। कई बार यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हैं।वह चोरी, डकैती या कोई भी अपराध करने को भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार जिद और सामाजिक दबाव में वह अपना विवेक खोकर किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। इस प्रवृत्ति का असर केवल परिवार के बजट पर नहीं, बल्कि बच्चों की सोच पर भी पड़ता है। यदि बच्चा अपनी पहचान को सिर्फ महंगे फोन और ब्रांडेड वस्तुओं से जोड़ने लगे, तो उसमें दिखावे और तुलना की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये हम सभी जानते है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से पढ़ाई, नींद, एकाग्रता प्रभावित होती है। इसका समाधान बच्चों को पूरी तरह तकनीक से दूर करना नहीं है, क्योंकि ऐसा कर पाना मुश्किल है । स्मार्टफोन आज शिक्षा, संपर्क और जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। जरूरत है कि माता-पिता, शिक्षक बच्चों को तकनीक और उपभोक्तावाद के बीच अंतर समझाएं। फोन खरीदते समय उसकी कीमत या ब्रांड के बजाय उसकी उपयोगिता, जरूरत और परिवार की आर्थिक क्षमता को देखे।इसका सीमित और जरूरत पूर्ति के लिए प्रयोग हो। युवा डिजिटल दुनिया और दिखावे में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि आज सोशल मीडिया ने तुलना, लोकप्रियता और उपभोग को जीवनशैली का हिस्सा बना दिया है । सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का चमकदार पक्ष दिखाते हैं। इससे युवाओं में तुलना की प्रवृत्ति बढ़ती है । ये देखकर वे अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। वर्तमान समय में युवा लाइक और फॉलोअर्स की संख्या को ही सब कुछ समझ ने लगे है। यह डिजिटल लोकप्रियता युवाओं के आत्मसम्मान से जुड़ने लग रही है। ज्यादा लाइक और फॉलोअर्स को ही आज सफलता का पैमाना माना जा रहा है। यह दिखावे की संस्कृति इस कदर युवाओं पर हावी हो गई है कि महंगे फोन, कपड़े, गाड़ियां, घूमने की जगहें और पार्टियां सोशल मीडिया पर नाम और प्रतिष्ठा के प्रतीक बन गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते विज्ञापन लगातार ऐसी चीजें सामने लाते हैं जो युवाओं में खरीदने और बेहतर दिखने की इच्छा पैदा करती हैं। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और सफलता बहुत आसान दिखाई देती है। इससे मेहनत, धैर्य और वास्तविक उपलब्धियों का महत्व कम होने लगता है। इस डिजिटल दुनिया में हजारों की संख्या में फ्रेंड होने के बावजूद आज कई युवा अपनी जिन्दगी में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। कई बार वास्तविक जीवन में संवाद की कमी को युवा डिजिटल दुनिया में समय बिताकर पूरा करने की कोशिश करते हैं।

आज असली चुनौती इस डिजिटल दुनिया के प्रभाव को समझना है जो एक नशे की तरह उन्हें अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। युवाओं को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी तरह से सच नहीं होती। जीवन की वास्तविक सफलता महंगे फोन, ब्रांडेड सामान, लाइक या फॉलोअर्स में नहीं, बल्कि परिश्रम, ज्ञान, चरित्र, परिवार और आत्म विश्वास में है। वर्तमान में माता पिता बच्चे की हर जरूरत पूरी करने को ही अपनी पेरेंटिंग समझ रहे है। कही न कही परिवार में संवाद कम हुआ है। हर घर में मोबाइल संस्कृति इस कदर हावी है कि चार लोग एक कमरे में बैठ कर भी अपने- अपने मोबाइल में बिजी दिखते है।माता-पिता को बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि किसी महंगे फोन, गैजेट्स का होना सफलता या श्रेष्ठता का पैमाना नहीं है। बच्चों को खेल, किताबों, रचनात्मक गतिविधियों और वास्तविक सामाजिक संबंधों के लिए भी पर्याप्त समय देना जरूरी है। स्मार्टफोन अपने आप में समस्या नहीं है;, समस्या तब पैदा होती है जब वस्तु जरूरत से बढ़कर मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक बन जाती है। बच्चों को तकनीक का समझदारी और संयम से इस्तेमाल करना सिखाना ही इस बढ़ती सनक का सबसे बेहतर समाधान है। बच्चे का व्यक्तित्व और संस्कार ही उसकी असली पहचान है। संवाद, समझाइश, समय और संयम के साथ परिवार के संस्कार उसे इस प्रकार के एडिक्शन और आभासी दुनिया से दूर रखने में सहायक हो सकते है।

विचार

विकसित भारत के लिए सिविल सेवा परीक्षा में चाहिए नया प्रतिमान

अभिषेक शुक्ल

भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान संरचना में औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक छाप दिखाई देती है। व्यापक सामान्य ज्ञान, अत्यधिक विस्तृत पाठ्यक्रम, स्मृति-आधारित तैयारी और वर्णनात्मक उत्तर लेखन पर निर्भरता इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यह व्यवस्था उस समय की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए उपयोगी रही होगी, लेकिन आज की जटिल और तकनीक-प्रधान शासन व्यवस्था में इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता स्पष्ट है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन की सफलता केवल आर्थिक विकास, आधुनिक आधारभूत संरचना और तकनीकी प्रगति पर निर्भर नहीं होगी। शासन की गुणवत्ता, प्रशासनिक संस्थाओं की क्षमता एवं योग्य मानव संसाधन का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टि से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान संरचना पर गंभीर और व्यापक पुनर्विचार आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सिविल सेवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं, बल्कि भविष्य के प्रशासनिक नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया है। चयन की यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो इक्कीसवीं सदी और विकसित भारत की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिभा, क्षमता, विशेषज्ञता और निर्णय-कौशल की पहचान कर सके। आज एक सिविल सेवक का कार्य केवल नियमों को लागू करना नहीं है। उसे जटिल नीतिगत समस्याओं का विश्लेषण करना है, उपलब्ध आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना है, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना है, सीमित संसाधनों में प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं और संकट की परिस्थितियों में त्वरित तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। इन क्षमताओं का मूल्यांकन केवल विस्तृत पाठ्यक्रम को याद करके वर्णनात्मक उत्तर लिखने की क्षमता से नहीं हो सकता। मुख्य परीक्षा की वर्णनात्मक प्रकृति में परीक्षक-भिन्नता की संभावना स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। अलग-अलग परीक्षकों द्वारा समान उत्तर की गुणवत्ता की व्याख्या और मूल्यांकन में अंतर हो सकता है। भाषा, प्रस्तुति, लेखन शैली, उदाहरणों के चयन और उत्तर की संरचना जैसे तत्व भी अंक निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च स्तरीय चयन प्रक्रिया में इस प्रकार की व्यक्तिपरकता को न्यूनतम करना आवश्यक है। इसका समाधान वर्णनात्मक परीक्षा को पूरी तरह समाप्त करने में नहीं, बल्कि उसके स्वरूप को अधिक योग्यता-आधारित बनाने में है। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी की समस्या-समझ, तार्किक विश्लेषण, उपलब्ध सूचना के उपयोग, प्राथमिकता निर्धारण, प्रमाण-आधारित निष्कर्ष और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इक्कीसवीं सदी में सूचना तक पहुंच का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इंटरनेट, डिजिटल भंडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तथ्यात्मक जानकारी तक पहुंच को पहले की तुलना में अत्यंत सरल बना दिया है। ऐसी स्थिति में केवल तथ्यों को स्मरण रखने की क्षमता को अत्यधिक महत्व देना चयन प्रक्रिया को उस वास्तविक क्षमता से दूर कर सकता है जिसकी आधुनिक प्रशासन में आवश्यकता है।

आधुनिक संज्ञानात्मक विज्ञान और मनोविज्ञान ने मानव की बौद्धिक क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए अनेक उपयोगी अवधारणाएं विकसित की हैं। संज्ञानात्मक लचीलापन, तार्किक विश्लेषण, निर्णय क्षमता, समस्या-समाधान, सीखने की क्षमता और सूचना-प्रसंस्करण जैसी क्षमताओं का वैज्ञानिक परीक्षण सिविल सेवा चयन को अधिक योग्यता-केंद्रित बना सकता है। परीक्षा में वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों पर आधारित परिस्थितिजन्य परीक्षण का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। अभ्यर्थियों के सामने ऐसी परिस्थितियां रखी जा सकती हैं जिनमें सीमित समय, अधूरी सूचना, परस्पर विरोधी हित और अनेक प्रशासनिक विकल्प मौजूद हों। इसके माध्यम से केवल अभ्यर्थी के ज्ञान का नहीं, बल्कि उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्राथमिकता निर्धारण और समस्या-समाधान क्षमता का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। ब्रिटेन की चयन प्रणाली में परिस्थितिजन्य निर्णय परीक्षण, कार्य-सामग्री परीक्षण और मूल्यांकन-केंद्र आधारित अभ्यास जैसे माध्यमों का उपयोग इसी प्रकार की क्षमताओं के आकलन के लिए किया जाता है। अभ्यर्थी को प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य दिए जाते हैं, जिनमें उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण, प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय क्षमता का परीक्षण होता है। अमेरिकी व्यवस्था में भर्ती अधिक पद-विशिष्ट है। अलग-अलग पदों और संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट ज्ञान, तार्किक क्षमता और व्यावहारिक योग्यता को महत्व दिया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्येक भूमिका के लिए समान प्रकार की प्रतिभा और समान प्रकार के परीक्षण को अनिवार्य मानना आवश्यक नहीं है। सिविल सेवा परीक्षा में सामान्यज्ञ अभिविन्यास की अपनी उपयोगिता है।

एक नजर

अगस्त में सेवानिवृत्त 17 रेलकर्मियों को मिला समापक भुगतान, सम्मानपूर्वक दी गई विदाई

बक्सर,एजेंसी। दानापुर मंडल में अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त हुए 17 रेलकर्मियों के लिए सोमवार को मंडल सभागार में समापक भुगतान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा) दानापुर राजीव कुमार ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को अंगवस्त्र एवं समापक भुगतान से संबंधित दस्तावेज सौंपकर सम्मानित किया तथा उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी अतुल कुमार ने की। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किए गए समापक भुगतान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। अपने संबोधन में अपर मंडल रेल प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि का सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने रेलकर्मियों को असुरक्षित स्थानों पर राशि निवेश नहीं करने तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी।

समारोह के दौरान सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन जीने के संबंध में एक्युप्रेशर एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के विभिन्न उपायों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर दानापुर मंडल के विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा ईसीआरईयू और एआईओबीसीआरई एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सेवानिवृत्त रेलकर्मियों के सेवाकाल की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सुखद और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दीं।

पंचायतों में लगा सहयोग शिविर, ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान

बक्सर। जिले के राजपुर प्रखंड की खरहना एवं बक्सर प्रखंड की अर्जुनपुर पंचायत में मंगलवार को आयोजित 'सहयोग शिविर' का अनुश्रवण किया गया। उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की उपस्थिति में अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने शिविर का जायजा लिया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं जरूरतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता ने शिविर में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं है, उनमें संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका निष्पादन करे। शिविर में ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं कल्याण सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और लाभुकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव अधिकारियों के सामने रखे। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविर प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट, डीएम ने तटवर्ती क्षेत्रों का किया निरीक्षण

बक्सर। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मंगलवार को जिला पदाधिकारी साहिला ने सिमरी अंचल के लाल सिंह का डेरा समेत तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संभावित बाढ़ की स्थिति, प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तथा प्रशासन की तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गंगा का जलस्तर मंगलवार को 60.17 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी स्तर 59.32 मीटर और खतरे का निशान 60.32 मीटर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 1948 में दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर 62.09 मीटर रहा है। खतरे के निशान से महज कुछ सेंटीमीटर नीचे पहुंच चुके जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने तटवर्ती और दियारा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सिमरी के अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि आबादी वाले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था के साथ नाविकों और प्रशिक्षित स्थानीय गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों के सुरक्षित आवागमन और राहत-बचाव कार्य में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन के अनुसार बक्सर, चौसा, सिमरी, चक्की और ब्रह्मपुर के दियारा क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तटबंधों पर 24 घंटे गश्त के साथ एसडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोरों को भी मुस्तैद रखा गया है। अंचलों द्वारा आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में नावों का परिचालन एवं व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मौसम सेवा केंद्र ने 02 सितंबर तक जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी संभावित आपात स्थिति में प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके।

बिहार में खुलेगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया कैंपस

युवा कलाकारों को राज्य में ही मिलेगा अभिनय और रंगमंच का पेशेवर प्रशिक्षण : सम्राट चौधरी

सद्भावना टुडे, संवाददाता

पटना। बिहार के युवा कलाकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) का नया कैंपस स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने बिहार में एनएसडी के नए कैंपस की स्थापना को सहमति प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनएसडी कैंपस की स्थापना राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक एवं नाट्य परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती कालिदास, रामवृक्ष बेनीपुरी और भिखारी ठाकुर जैसी महान विभूतियों की कर्मभूमि रही है। राज्य की लोक नाट्य एवं प्रदर्शन कला की अपनी विशिष्ट और गौरवशाली परंपरा रही है।

अभिनय से स्टेजक्राफ्ट तक मिलेगा प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसडी कैंपस के स्थापित होने से बिहार के युवा कलाकारों को अपने ही राज्य में पेशेवर नाट्य प्रशिक्षण, अभिनय, स्टेजक्राफ्ट, प्रदर्शन कला और उन्नत शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता भी काफी हद तक कम होगी। उन्होंने कहा कि एनएसडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की मौजूदगी से बिहार की पारंपरिक लोक नाट्य विधाओं और आधुनिक रंगमंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ नई पीढ़ी के कलाकारों को आधुनिक तकनीक और रंगमंच की बारीकियों से परिचित कराने में मदद मिलेगी।

भूमि उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार, भवन लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश

एनएसडी कैंपस की स्थापना के लिए बिहार सरकार उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा भवन निर्माण की स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश भी बिहार सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान की शीघ्र स्थापना के लिए राज्य सरकार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई और हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार नाट्य कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और समन्वय के लिए पहले से ही बिहार संगीत नाट्य अकादमी के माध्यम से कार्य कर रही है। ऐसे में एनएसडी कैंपस की स्थापना राज्य के सांस्कृतिक प्रयासों को नई गति और मजबूती प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय रंगमंच के मानचित्र पर और मजबूत होगी बिहार की पहचान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनएसडी कैंपस की स्थापना केवल एक नए संस्थान का निर्माण नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत, युवा प्रतिभाओं और आधुनिक रंगमंच के भविष्य में निवेश है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से यह संस्थान बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के साथ राज्य को देश के रंगमंच के मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

30 सितंबर तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य, फसलों की होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग : विजय कुमार सिन्हा

पटना। बिहार की कृषि व्यवस्था को डेटा-आधारित, पारदर्शी एवं आधुनिक बनाने की दिशा में कृषि विभाग द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राज्य के सभी 38 जिलों में शारदीय (खरीफ) 2026 के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे जारी है। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष खरीफ मौसम में कुल 2 करोड़ 62 लाख 84 हजार 716 प्लॉट के सर्वे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 41 लाख प्लॉट का डिजिटल सर्वे पूरा किया जा चुका है।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 13 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुआ है और इसे 30 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वे के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे आने वाले समय में किसानों एवं कृषि विभाग को मोबाइल के माध्यम से फसल संबंधी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खेत, फसल तथा उसकी जियो-टैग्ड तस्वीर सहित आवश्यक विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज किए जा रहे हैं। इससे यह सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि राज्य के किस क्षेत्र में, किस किसान के किस प्लॉट में कौन-सी फसल बोई गई है। सर्वे में धान सहित खरीफ की प्रमुख फसलों, बागवानी फसलों तथा एक माह से अधिक समय पूर्व रोपी गई फसलों को भी शामिल किया गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे से फसल आच्छादन का अधिक सटीक एवं व्यवस्थित आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

इसके माध्यम से मौसमवार एवं फसलवार आच्छादन का आकलन करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता के पूर्वानुमान में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए राज्य के सभी जिलों में कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। जिलों में आकस्मिक क्षेत्र भ्रमण के साथ-साथ दैनिक एवं साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सर्वे कार्य की लगातार समीक्षा की जा रही है।

सिमरी सीएचसी व प्रखंड-अंचल कार्यालय में डीएम का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

बक्सर। जिला पदाधिकारी श्रीमती साहिला ने मंगलवार को सिमरी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, साफ-सफाई, चिकित्सकों एवं कर्मियों की उपस्थिति तथा कार्यालयों में कार्य संस्कृति की विस्तृत समीक्षा की गई। कई कर्मियों के निर्धारित समय के बाद पहुंचने और अस्पताल की व्यवस्थाओं में कमियां मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएचसी सिमरी के निरीक्षण के दौरान डीएम ने बायोमैट्रिक उपस्थिति की जांच की। इस दौरान कई चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं मिले और विलंब से अस्पताल पहुंचे। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने सिविल सर्जन को संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित रखने का निर्देश दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य केंद्र जैसी महत्वपूर्ण संस्था में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की समय पर उपस्थिति बेहद जरूरी है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ड्यूटी के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड एवं शौचालय में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। डीएम ने अस्पताल परिसर की नियमित सफाई, मरीजों के लिए बेहतर वातावरण तथा स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया। वहीं, परिवार नियोजन परामर्श कक्ष बंद पाया गया। इस पर डीएम ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार मरीजों को मिलनी चाहिए और किसी भी सेवा में अनावश्यक व्यवधान नहीं होना चाहिए। डीएम ने मरीजों एवं उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर में 'मे आई हेल्प यू' काउंटर तत्काल संचालित करने का निर्देश दिया।

सबौर के इंग्लिश गाँव में गंगा का तांडव, रात भर में नदी में समाए आधा दर्जन आशियाने

भागलपुर। जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गाँव में गंगा का कटाव अब स्थानीय लोगों के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि उनके जीवन भर के सपनों के उजड़ने की दर्दनाक दास्तान बन चुका है। सोमवार की देर रात से लेकर मंगलवार की अहले सुबह तक गंगा की तेज धारा ने भयानक कहर बरपाया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पक्के मकान देखते ही देखते नदी में समा गए। किसी की गृहस्थी बही, तो किसी की जीवन भर की जमा-पूंजी गंगा की तेज लहरों की भेंट चढ़ गई। पीड़ित परिवारों के पास अब सिर छिपाने तक की जगह नहीं बची है।

तबाही का मंजर इतना खौफनाक था कि लोग बेबस होकर अपनी आँखों के सामने अपने आशियानों को जमींदोज होते देखते रहे। कटाव के मुहाने पर खड़े भगवान यादव ने खतरे की गंभीरता को देखते हुए आनन-फानन में अपना घर खाली कर दिया है। वहीं, गाँव के मणि भूषण चौबे ने भी अपना पूरा मकान खाली कर लिया है। गाँव के कई अन्य घर अब भी कटाव के मुहाने पर खड़े हैं, जिससे ग्रामीणों में यह खौफ है कि न जाने अगली सुबह उनका घर बचेगा भी या नहीं। पीड़ित राधे साह ने रुंधे गले से अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, 'हमारा पूरा घर गंगा में विलीन हो गया। जब तक परिवार के लोग कुछ समझ पाते और सामान निकालते, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तन पर पहने कपड़ों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। गहने-जेवरात, फ्रिज, टीवी, कपड़े और घर में रखे पैसे सब कुछ गंगा की तेज धारा में बह गए।' उल्लेखनीय है कि इंग्लिश गाँव में गंगा का यह रौद्र रूप नया नहीं है। वर्ष 2023 और 2024 में भी यहाँ गंगा ने जमकर तबाही मचाई थी। तब प्रशासन

की ओर से करोड़ों रुपये की लागत से कटावरोधी कार्य कराया गया था। लेकिन आज हालात यह हैं कि वह पूरा का पूरा कटावरोधी ढांचा खुद गंगा में विलीन हो चुका है। ग्रामीण अब इस कार्य की गुणवत्ता और सरकारी दावों पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। गाँव में मची इस भारी तबाही के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग की टीम हरकत में आई है। कटाव को रोकने के लिए युद्धस्तर पर गंगा किनारे बालू से भरी बोरियां (फ्लड फाइटिंग वर्क) डाली जा रही हैं। हालांकि, प्रशासनिक मुस्तैदी के बावजूद स्थानीय ग्रामीण इस व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि गंगा की इतनी तेज धारा के सामने महज बालू की बोरियां कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगी। यदि तत्काल प्रभाव से कोई मजबूत और ठोस तकनीकी उपाय नहीं किया गया, तो पूरा इंग्लिश गाँव जल्द ही इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा।

जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड ने रचा सफलता का नया अध्याय

सहरसा,एजेंसी। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक श्लोक कुमार की अध्यक्षता में जीविका द्वारा संपोषित माँ जानकी जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड, रौता खेम, सौरबाजार की वार्षिक आम सभा 2025-26 का आयोजन समिति कार्यालय परिसर में किया गया।

कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला परियोजना प्रबंधक श्लोक कुमार, समिति की अध्यक्ष रौशन कुमारी, निदेशक मंडल के सदस्यों, प्रशिक्षण अधिकारी रंजन कुमार एवं अनुप्रिया पंजियार तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक आनंद प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आम सभा को संबोधित करते हुए समिति की अध्यक्ष रौशन कुमारी ने बताया कि संकुल संघ से जुड़े पांच पंचायतों में 1271 स्वयं सहायता समूह एवं 70 ग्राम संगठनों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा तथा छूटे हुए ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की गई है। समिति की सचिव नीलम देवी ने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजना आम सभा के समक्ष प्रस्तुत की। वहीं, कोषाध्यक्ष अंजलि देवी ने वार्षिक लेखा-परीक्षण, आय-व्यय का विवरण एवं आगामी बजट प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। संकुल संघ के लेखापाल सुमन सिंह ने

बताया कि वर्तमान में 70 ग्राम संगठनों के माध्यम से 15,919 सदस्य संकुल संघ से जुड़े हैं। संघ को आरंभिक पूंजीकरण निधि के रूप में 7.33 करोड़ रुपये, ब्याज के रूप में 25.35 लाख रुपये तथा बैंक ब्याज के रूप में 1.44 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में समिति द्वारा 26.79 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया गया। उन्होंने बताया कि जीविका के माध्यम से 993 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देकर विभिन्न कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रखंड परियोजना प्रबंधक आनंद प्रकाश ने सौरबाजार प्रखंड में महिलाओं के विकास एवं जीविका द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सामुदायिक संगठनों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीविका कर्मियों सहित बड़ी संख्या में अंशधारी दीदियां उपस्थित रहीं।

बापूधाम महोत्सव में पूर्वी चंपारण को 285 करोड़ की सौगात, बरियारपुर में बनेगा मेडिकल कॉलेज

मोतिहारी। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंगलवार को बापूधाम महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी चंपारण के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने करीब 285 करोड़ की 145 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन योजनाओं से जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, खेल और आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बरियारपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। वहीं, मोतिहारी में तारामंडल का निर्माण जल्द शुरू होगा। पीपराकोठी में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय को आम लोगों की मांग पर अब बरियारपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नेहरू स्टेडियम में वर्तमान में संचालित केंद्रीय विद्यालय के स्थान पर इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा मोतिहारी में 20 करोड़ रुपये की लागत से अटल कला भवन का निर्माण कराया जाएगा। तेतरिया के कोठिया में एक्वाकल्चर पार्क, मत्स्य समृद्धि क्लस्टर और फिश प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण भी जल्द शुरू करने की बात कही गई। मोतिहारी में मौजूदा मदर डेयरी से बड़े नए मदर डेयरी प्लांट की स्थापना की योजना भी है। लंबे समय से बंद चीनी मिल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे दोबारा शुरू करने की दिशा में जल्द काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मोतीझील के किनारे रोईंग क्लब से पावर हाउस, चीनी मिल, शिव मंदिर और अनाथ आश्रम होते हुए चिकनीघाट-अगरवा तक सड़क एवं नाला निर्माण कराया जाएगा। इस मार्ग को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करने की योजना है। सड़कों के विकास और विस्तार के तहत मोतिहारी-तुरकौलिया-गोविंदगंज पथ में रघुनाथपुर पुल से बालगंगा तक 3.2 किलोमीटर सड़क का विकास किया जाएगा। वहीं, पीपरा एनएच-27 से राजपुर चौक भाया कल्याणपुर तक 17 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। शीतलपुर से रमडीहा भाया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज पथ और अरेराज मंदिर जाने वाली प्रमुख सड़कों के विकास की भी घोषणा की गई। मोतिहारी को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के आवेदनों के निष्पादन में देरी को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 11वें दिन, 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 21वें दिन और 25 दिन में भी कार्रवाई नहीं होने पर 30वें दिन संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी-कर्मी को निलंबित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी शिक्षित होगी, तभी बिहार समृद्ध होगा। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) का नया कैंपस स्थापित किए जाने की भी जानकारी दी। बताया कि केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और भवन निर्माण की स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश वहन करेगी।

एक नजर

राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में मुरादाबाद के विवान गुप्ता ने जीता स्वर्ण पदक

मुरादाबाद,एजेंसी। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित द्वितीय मिनी अंडर-11 और जूनियर अंडर-17 नेशनल नॉर्थ जोन रोल वॉल चैंपियनशिप 2026 में मुरादाबाद के प्रतिभावान खिलाड़ी विवान गुप्ता ने अंडर-17 वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर मुरादाबाद का नाम रोशन किया। डिस्ट्रिक्ट रोल वॉल एसोसिएशन मुरादाबाद की जिला सचिव रिंपी सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता 29 से 31 अगस्त तक स्केटिंग रिंक, परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित हुई। गोल्डन गेट स्कूल के छात्र विवान गुप्ता का चयन मुरादाबाद से इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। विवान ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक हासिल किया। विवान की इस उपलब्धि से मुरादाबाद के खेल जगत और विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। उनकी सफलता पर डिस्ट्रिक्ट रोल वॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु मिश्रा, जिला सचिव रिंपी सिंह, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों, कोच एवं टीम सदस्यों ने विवान को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने कहा कि विवान की यह उपलब्धि मुरादाबाद के लिए गर्व का विषय है और उनकी सफलता जिले के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। विवान गुप्ता की इस शानदार उपलब्धि पर पूरे मुरादाबाद को गर्व है।

चाइना मास्टर्स : मुकाबला पूरा किए बिना ही बाहर हुई हरिहरन-अर्जुन की भारतीय जोड़ी

नई दिल्ली। भारत की विश्व नंबर-24 पुरुष युगल जोड़ी हरिहरन अम्साकरुणन और एमआर अर्जुन को चाइना मास्टर्स के पहले दौर में मुकाबला पूरा किए बिना बाहर होना पड़ा। भारतीय जोड़ी मंगलवार को चीन की विश्व नंबर-10 जोड़ी चेन बो यांग और लियू यी के खिलाफ पहले गेम के इंटरवल पर रिटायर हो गई। चेन और लियू ने मुकाबले की तेज शुरुआत करते हुए 5-1 की बढ़त बना ली और जल्द ही स्कोर 7-3 कर दिया। हालांकि, हरिहरन और अर्जुन ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। इसके बाद चीनी जोड़ी ने फिर बढ़त हासिल की और पहले गेम के ब्रेक तक 11-8 की बढ़त बना ली। इंटरवल के दौरान हरिहरन और अर्जुन ने मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके साथ ही चेन बो यांग और लियू यी को विजेता घोषित कर दिया गया और उन्होंने अगले दौर में जगह बना ली। भारतीय जोड़ी के रिटायर होने की वजह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सकी। अगले दौर में चेन और लियू का सामना मलेशिया की आरोन चिया और सोह वूई यिक की जोड़ी से होगा। मलेशियाई जोड़ी ने जापान के हिरोकी ओकामुरा और क्योहेई यामाशिता को 18-21, 21-12, 21-15 से हराया। हरिहरन और अर्जुन ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतिम-32 दौर में हार के बाद चाइना मास्टर्स में हिस्सा लिया था। भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्युक और की डोंग जू के खिलाफ 21-17, 21-14 से हार मिली थी। अब हरिहरन और अर्जुन का अगला पड़ाव जापान होगा, जहां वे इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अर्जुन 2023 एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम का हिस्सा थे।

चाइना मास्टर्स : उन्नति हुड्डा का पहले दौर में सफर खत्म, किम गा-उन से मिली हार

नई दिल्ली। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को चाइना मास्टर्स के पहले दौर में दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर-12 खिलाड़ी किम गा-उन से हार का सामना करना पड़ा। किम ने उन्नति को सीधे गेमों में 21-10, 21-18 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। किम ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और पहले गेम के ब्रेक तक 11-3 की बढ़त हासिल कर ली। ब्रेक के बाद भी कोरियाई खिलाड़ी ने उन्नति को वापसी का मौका नहीं दिया और स्कोर 20-10 करने के बाद पहला गेम 21-10 से अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में उन्नति ने बेहतर शुरुआत की। उन्होंने आक्रामक खेल दिखाते हुए 3-0 की बढ़त बना ली। हालांकि किम ने जल्द ही वापसी करते हुए स्कोर 8-8 से बराबर कर दिया और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। उन्नति ने लगातार संघर्ष करते हुए स्कोर 13-13 से बराबर कर दिया और मुकाबले को रोमांचक बना दिया। हालांकि निर्णायक क्षणों में किम ने अपना धैर्य बनाए रखा और बढ़त हासिल करते हुए दूसरा गेम 21-18 से जीत लिया। इस जीत के साथ किम ने 21-10, 21-18 से मुकाबला अपने नाम कर उन्नति हुड्डा के चाइना मास्टर्स अभियान को पहले ही दौर में समाप्त कर दिया।

हरिहरन-अर्जुन ने मैच छोड़ा

इससे पहले दिन में भारत के विश्व नंबर-24 पुरुष युगल खिलाड़ी हरिहरन अम्साकरुणन और एम.आर. अर्जुन को भी अपने पहले दौर के मुकाबले में निराशा हाथ लगी। चीन की विश्व नंबर-10 जोड़ी चेन बो यांग और लियू यी के खिलाफ मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने पहले गेम के इंटरवल पर मैच से हटने का फैसला किया।

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, संजू सैमसन की वापसी

नई दिल्ली,एजेंसी। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों टीमों के बीच सीरीज के तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा मुकाबला 17 सितंबर को होगा। भारतीय टीम में कोई बड़ा चौंकाने वाला बदलाव नहीं किया गया है। जिम्बाब्वे दौरे से बाहर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी को फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन टीम में शामिल किया गया है।पैर की चोट से उबर चुके वरुण चक्रवर्ती की भी टीम में वापसी हुई है। हालांकि, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और इस सीरीज में नहीं खेलेंगे।

भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। टीम में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के अलावा ईशान किशन, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ यह सीरीज भारत के लिए टी-20 प्रारूप में खोया हुआ आत्मविश्वास हासिल करने के लिहाज से अहम होगी। टी-20 विश्व चैंपियन भारत को हाल में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को टी-20 सीरीज में 4-0 से हराया था, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। हालांकि, भारत ने इसके बाद जिम्बाब्वे को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हराकर वापसी

की थी। दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने इस साल भारत में हुए टी-20 विश्व कप के बाद से कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। विश्व कप में उसने चार में से दो मैच जीते थे, लेकिन सुपर-8 चरण में जगह नहीं बना सका था। भारत और अफगानिस्तान की टीमें आखिरी बार जून में भिड़ी थीं, जब भारत ने एकमात्र टेस्ट में एक पारी और 300 रन से जीत दर्ज करने के बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी अफगानिस्तान का 3-0 से सफाया किया था।

भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा***

नोट: फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन।

पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव, मिस्बाह-उल-हक ने चयन समिति से दिया इस्तीफा

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट में इंग्लैंड दौरे के बीच टेस्ट टीम में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार मिस्बाह ने लाहौर स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में बल्लेबाजी सलाहकार के पद से भी हटने का फैसला लिया है। उनका यह कदम इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बीच पीसीबी के टीम और कोचिंग स्टाफ में फेरबदल किये जाने के एक दिन बाद आया है।

पाकिस्तान तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 से पीछे है। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में उसे 194 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने तीसरे टेस्ट से पहले टेस्ट टीम से सात खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। इनमें मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक, सलमान आगा, अली उस्मान, आमेर जमाल, अवैस जफर और खुर्रम शहजाद शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया गया। पीसीबी ने पांच अनकैप्ड खिलाड़ियों अराफात मिन्हास, मोहम्मद इमरान जूनियर, साद बैग, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह को टेस्ट टीम में शामिल किया है। इनके अलावा साइम अयूब और अब्दुल्ला फजल भी टीम से जुड़ेंगे। सफेद गेंद की टीम के मुख्य कोच माइक हेसन और गेंदबाजी कोच एश्ले नॉफ्के को टेस्ट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल किया गया है।

तीसरा टेस्ट 9 सितंबर से एजबेस्टन में खेला जाना है। 2017 में पाकिस्तान के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में शामिल मिस्बाह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पीसीबी में कई भूमिकाएं निभाईं। 2019 में उन्हें मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता की दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अक्टूबर 2020 में उन्होंने मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ दिया था, जबकि अगले साल मुख्य कोच की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह पीसीबी से अलग-अलग भूमिकाओं में जुड़े रहे। 2024 में उन्हें पुरुषों की चैंपियंस कप प्रतियोगिता के पांच मेंटर्स में शामिल किया गया था। उन्होंने घरेलू महिला टीमों को भी मेंटर किया। पिछले महीने मुल्तान में आयोजित 50 ओवर की नेशनल चैंपियंस कप में मिस्बाह ने पाकिस्तान गोल्ड टीम को कोचिंग दी थी, जिसने शाहीन अफरीदी की कप्तानी में खिताब जीता। इसी साल मार्च में मिस्बाह को चार सदस्यीय चयन समिति का हिस्सा बनाया गया था।

एशियाई खेलों की तैयारी में जुटे भारतीय एथलीट, बेंगलुरु में 'स्मार्ट ट्रैक' से मिल रहा रियल टाइम डेटा

बेंगलुरु। एशियाई खेल-2026 की तैयारियों के तहत भारतीय मध्य और लंबी दूरी के एथलीटों का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में चल रहा है। आठ सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में एथलीटों को अत्याधुनिक 'स्मार्ट ट्रैक' की सुविधा भी मिल रही है, जो प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शन का रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है।

लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत स्वीकृत इस शिविर में 800 मीटर धावक कृष्ण कुमार, स्टीपलचेज धावक अविनाश साबले, हाई जंप खिलाड़ी आदर्श राम और सुप्रिया बी, डेकाथलॉन खिलाड़ी थौफीक एन, मध्य एवं लंबी दूरी की धावक पारुल चौधरी तथा रेस वॉकर मंजू रानी और प्रियंका हिस्सा ले रही हैं। ये सभी एशियाई खेलों के लिए स्वीकृत भारत की 73 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का हिस्सा हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक आइची-नागोया में आयोजित की जाएंगी। बेंगलुरु साई केंद्र में मौजूद स्मार्ट ट्रैक पर प्रशिक्षण के दौरान एथलीटों की गति, स्प्लिट टाइम, कुल समय, स्ट्राइड की लंबाई और स्ट्राइड की आवृत्ति जैसी जानकारियां तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। साई एनसीओई बेंगलुरु के एथलेटिक्स कोच सुरेश कुमार ने कहा कि यह भारत में अपनी तरह की विशेष सुविधा है।

उनके मुताबिक, एथलीट के दौड़ने के साथ ही ट्रैक पर लगे टाइमिंग गेट रियल टाइम स्पीड और स्प्लिट टाइम दर्ज करते हैं। इससे कोच और खिलाड़ी प्रदर्शन का अधिक सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। स्मार्ट ट्रैक का इस्तेमाल राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पैरा-एथलेटिक्स पदक विजेताओं दिलीप महादू गवित और मोहम्मद बासिल ने भी ग्लासगो खेलों से पहले प्रशिक्षण के दौरान किया था। दोनों ने पुरुषों की 100 मीटर टी47 स्पर्धा में क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक जीते थे। बेंगलुरु में यह स्मार्ट ट्रैक वर्ष 2024 में स्थापित किया गया था और तब से यहां प्रशिक्षण लेने वाले शीर्ष एथलीट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैक के सीधे हिस्से और मोड़ पर टाइमिंग गेट लगाए गए हैं, जिससे दौड़ के अलग-अलग चरणों का विश्लेषण किया जा सकता है। एक मोबाइल एप के माध्यम से भी आंकड़ों को तुरंत देखा और बाद में उनका विश्लेषण किया जा सकता है।

काशी रुद्रास ने मेरठ को 56 रन से रौंदा, यूपी टी20 लीग के टॉप-4 में जगह पक्की

कानपुर,एजेंसी। मौजूदा चैंपियन काशी रुद्रास ने यूपी टी-20 लीग 2026 के प्लेऑफ की दौड़ में शानदार वापसी करते हुए मंगलवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेरठ मावेरिक्स को 56 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ लीग चरण समाप्त होते ही टूर्नामेंट की शीर्ष चार टीमों की तस्वीर भी साफ हो गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्रास ने 20 ओवर में चार विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान करण शर्मा ने 40 गेंदों पर 57 रन की जिम्मेदार पारी खेली, जबकि वैभव जायसवाल ने 24 गेंदों में 33 रन बनाकर टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 75 रन जोड़े।

इसके बाद उपेंद्र यादव ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 29 गेंदों में नाबाद 57 रन ठोक दिए। उनकी पारी में चार चौके और पांच छक्के शामिल रहे। इस विस्फोटक पारी की बदौलत काशी ने मेरठ के सामने 176 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज स्वस्तिक चिकारा खाता खोले बिना ही कार्तिक यादव का शिकार बन गए। कार्तिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर तीन विकेट लिए और मेरठ के शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मेरठ की टीम 13 ओवर में 70 रन पर पांच विकेट गंवा चुकी थी। दिव्यांश राजपूत ने 31 गेंदों में 39 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन 16वें ओवर में ऋषभ राजपूत ने उन्हें हिट-विकेट आउट कर दिया। इसी ओवर की अगली गेंद पर यश गर्ग भी पवेलियन लौट गए। 17वें ओवर की

पहली गेंद पर इम्पैक्ट प्लेयर संगम सिंह ने विकेट लेकर दो ओवरों में फैली टीम हैट्रिक पूरी की। मेरठ की पूरी टीम 19.2 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। ऋषभ राजपूत ने 13 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि अटल बिहारी विपिन राय को दो सफलताएं मिलीं। इस जीत के साथ काशी रुद्रास ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई। मेरठ मावेरिक्स 15 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि लखनऊ फाल्कन्स 13 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नोएडा किंग्स 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही। वहीं गोरखपुर लायंस और कानपुर सुपरस्टार्स का अभियान समाप्त हो गया।

बंगाल छोड़ने का मन बना चुके युवा शूटर अभिनव साव को मिला 25 लाख रुपये का सम्मान

कोलकाता,एजेंसी। देश और विदेश में कई स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले आसनसोल के युवा शूटर अभिनव साव को आखिरकार अपने ही राज्य में बड़ा सम्मान मिला है। कभी पश्चिम बंगाल से पर्याप्त सहयोग और पहचान नहीं मिलने से निराश होकर दूसरे राज्य से खेलने का विचार बना चुके थे। अभिनव को अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हाथों 'अटल खेल सम्मान' के साथ सरकार की ओर से 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

उल्लेखनीय है कि महज 18 वर्ष की उम्र में शूटिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके अभिनव साव ने जर्मनी में आयोजित विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस उपलब्धि के दौरान उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। राष्ट्रीय खेलों में भी उनके नाम कांस्य पदक दर्ज है। अभिनव का कहना है कि विदेशों में पदक जीतने के बावजूद उन्हें अपने राज्य से अपेक्षित सहयोग और पहचान नहीं मिल रही थी। इसी कारण उन्होंने बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की तलाश में अमृतसर के एक कॉलेज में दाखिला लिया था और भविष्य में किसी दूसरे राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर विचार किया था। लेकिन राज्य सरकार की ओर से मिले आश्वासन और सम्मान के बाद अब उनका फैसला बदल गया है। अभिनव ने कहा कि अपने घर और अपने राज्य से मिलने वाली पहचान का एहसास अलग होता है

और अब वह पश्चिम बंगाल के लिए ही खेलना चाहते हैं। मिली जानकारी के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले राज्य के नए खेल मंत्री डॉ. इंद्रनील खां ने अभिनव और उनके पिता से बातचीत की थी। इस दौरान सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का भरोसा दिया गया, जिसके बाद साव परिवार ने बंगाल छोड़ने के विचार को बदल दिया। अभिनव साव फिलहाल जूनियर वर्ग में देश के नंबर-1 और सीनियर वर्ग में छठे स्थान पर हैं। अब उनकी नजर वर्ष 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स ओलंपिक पर है और वह उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

अभिनव के पिता रूपेश कुमार साव ने कहा कि उनका स्वयं शूटर बनने का सपना आर्थिक अभाव के कारण पूरा नहीं हो सका था। इसलिए बेटे के जन्म के बाद ही उन्होंने उसे एक सफल शूटर बनाने का लक्ष्य तय कर लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिली आर्थिक सहायता से अभिनव को और बेहतर तथा उन्नत प्रशिक्षण मिल सकेगा। परिवार को उम्मीद है कि आधुनिक प्रशिक्षण और विदेशी कोचों के मार्गदर्शन से अभिनव भविष्य में देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। राज्य सरकार से मिले इस सम्मान के बाद अब युवा शूटर का लक्ष्य ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करना है।

आईसीसी महिला टी-20 रैंकिंग में चमारी अटापट्टू का जलवा, तीनों वर्गों में बनाया करियर बेस्ट रिकॉर्ड

दुबई,एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुए महिला एशिया कप के शुरुआती मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन का असर ताजा आईसीसी महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में भी देखने को मिला है। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऑलराउंडर तीनों वर्गों में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ श्रीलंका की नौ विकेट की जीत में अटापट्टू ने सिर्फ 25 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए और तीन ओवर में 10 रन देकर एक विकेट भी लिया। इस प्रदर्शन के बाद वह बल्लेबाजी रैंकिंग में छठे स्थान पर बनी हुई हैं, जबकि गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर 33वें स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑलराउंडरों की सूची में वह तीसरे स्थान पर कायम हैं। अटापट्टू के खाते में अब बल्लेबाजी में 734, गेंदबाजी में 552 और ऑलराउंडर वर्ग में 405 रेटिंग अंक हैं, जो तीनों श्रेणियों में उनका करियर बेस्ट है।

श्रीलंका की सलामी बल्लेबाज इमेशा दुलई ने भी चार स्थान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 18वीं रैंकिंग हासिल की है। संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 18 गेंदों में 25 रन की पारी ने उन्हें 625 रेटिंग अंक तक पहुंचाया। गेंदबाजी में श्रीलंका की मिथाली अयोध्या ने 18 स्थान की बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ तीन विकेट लेकर मेजबान टीम को 79 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। वह अब 70वें स्थान पर हैं और उनके खाते में करियर के सर्वश्रेष्ठ 444 रेटिंग अंक हैं। सुगंधिका कुमारी दो विकेट

के प्रदर्शन के बाद पांच स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गई हैं। थाईलैंड के खिलाफ भारत की जीत में तीन विकेट लेने वाली भारतीय तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने 18 रन देकर तीन विकेट लिए थे, जिसके बाद वह 38 स्थान की छलांग लगाकर 112वें स्थान पर पहुंच गई हैं। थाईलैंड की नन्नापत कोंचारोएनकाई भारत के खिलाफ 48 गेंदों में 41 रन की पारी के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं भारत के खिलाफ तीन विकेट लेने वाली सुलीपॉर्न लाओमी पांच स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 63वें स्थान पर पहुंची हैं। बांग्लादेश की सोभाना मोस्तारी भी एक स्थान की बढ़त के साथ 39वें स्थान पर पहुंच गई हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के खिलाफ 71 रन की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके खाते में करियर के सर्वश्रेष्ठ 500 रेटिंग अंक हैं। वहीं मरूफा अख्तर दो स्थान की बढ़त के साथ 37वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

एक नजर

नेपाल त्रासदी पर ब्रिटिश पीएम बर्नहैम ने जताया दुख, बोले- जलवायु संकट की भयावह तस्वीर

लंदन,एजेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने नेपाल-चीन सीमा पर आई भीषण आपदा पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि ब्रिटेन इस संकट की घड़ी में नेपाल सरकार और प्रभावित ब्रिटिश नागरिकों की हरसंभव मदद कर रहा है। उन्होंने इस त्रासदी को जलवायु संकट के गंभीर प्रभावों से जोड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में बर्नहैम ने कहा कि नेपाल-चीन सीमा से सामने आई तबाही की तस्वीरों से पूरा ब्रिटेन स्तब्ध और दुखी है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों और लापता लोगों के परिवारों के साथ हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बताया कि विदेश मंत्री नेपाल सरकार और क्षेत्र में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संकट के दौरान ब्रिटेन की ओर से सहयोग जारी रखने का भरोसा दिलाया। बर्नहैम ने आपदा को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से जोड़ते हुए कहा कि यह जलवायु संकट का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने भी इस वर्ष संभवत: अब तक की सबसे गर्म गर्मियों में से एक का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। बर्नहैम ने यह भी पुष्टि की कि वह नवंबर में तुर्किये में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी-31 में हिस्सा लेंगे।

गाजा में इजराइली हमलों की हमास ने की निंदा, सीजफायर उल्लंघन का लगाया आरोप

गाजा,एजेंसी। गाजा पट्टी में मंगलवार को हुए इजराइली हमलों को लेकर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संगठन का दावा है कि इन हमलों में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी व्यापक सैन्य कार्रवाई का हिस्सा बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। हमास ने एक बयान में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर जानबूझकर और लगातार हमले करने का आरोप लगाया। संगठन के मुताबिक, मौजूदा घटनाक्रम यह संकेत देता है कि सीजफायर समझौते के तहत तय दायित्वों का पालन नहीं किया जा रहा है। हमास ने कहा कि गाजा में सामने आ रही स्थिति को अब अलग-अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उसके अनुसार, लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई एक व्यापक नीति का हिस्सा बनती जा रही है। संगठन ने सीजफायर समझौते में मध्यस्थता करने वाले देशों और इसके गारंटर पक्षों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। हमास ने उनसे इजराइली सरकार पर दबाव डालकर हमले रोकने और समझौते की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा। हमास ने संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भी कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि गाजा में लगातार हो रही हिंसा के बीच जवाबदेही तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

आईआरजीसी से कारोबार करने वालों पर अमेरिका लगाएगा नए प्रतिबंध : अमेरिकी वित्त मंत्री

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वाशिंगटन उन लोगों और संस्थाओं के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका आईआरजीसी की संपत्तियों का भी पता लगा रहा है। जी20 वित्तीय बैठक के दौरान बेसेंट ने ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में ईरान की नौसेना, वायुसेना और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है। उनका यह भी दावा था कि ड्रोन बनाने वाली ईरान की अधिकांश फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाया गया है। बेसेंट ने कहा कि ईरान इस समय सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने अमेरिकी रणनीति को आर्थिक दबाव बढ़ाने वाली मुहिम के रूप में पेश करते हुए कहा कि वाशिंगटन ईरानी शासन पर आर्थिक दबाव और तेज करेगा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि प्रतिबंधों का दायरा केवल ईरानी संस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान या उसकी सेना के साथ कारोबार करने वाले तीसरे देशों के कारोबारी और वित्तीय संस्थान भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिका पहले ही ईरान से जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहा है और इस सप्ताह एक ईरानी बैंक पर नए प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना भी जताई गई है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन आईआरजीसी की वैश्विक संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ईरान की वित्तीय क्षमता और उसके सैन्य ढांचे को आर्थिक रूप से कमजोर करना है।

ब्रिटेन की राजनीति से पूर्व पीएम स्टार्मर लेंगे विदाई, संसद की सदस्यता से इस्तीफा का फैसला

लंदन,एजेंसी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ब्रिटिश राजनीति में उनका 11 साल लंबा संसदीय सफर समाप्त होने जा रहा है। स्टार्मर ने अपने स्थानीय अखबार कैम्डेन न्यू जर्नल से कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स छोड़ने का यह उनके लिए 'सही समय' है। स्टार्मर वर्ष 2015 में पहली बार सांसद बने थे। इससे पहले वह ब्रिटेन के

सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष कानूनी अधिकारी के रूप में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशंस की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। वर्ष 2019 में उन्होंने लेबर पार्टी की कमान संभाली और 2024 के आम चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर प्रधानमंत्री बने। हालांकि, प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अपेक्षित जनसमर्थन कायम नहीं रख सका। जनमत सर्वेक्षणों में लोकप्रियता गिरने के बाद उन्होंने जून 2026 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की थी। उनके बाद एंडी बर्नहैम ने प्रधानमंत्री पद संभाला। स्टार्मर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात रही, लेकिन अब वह अंतरराष्ट्रीय मामलों, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के प्रयास जारी रखने की भी बात कही। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए स्टार्मर ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, सार्वजनिक सेवाओं के पुनर्निर्माण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन की छवि मजबूत करने की दिशा में काम किया।

नेपाल त्रासदी के बाद अब तक मिले 987 शव

581 अज्ञात शव दफन किये गए

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में आई बाढ़ के बाद अब तक 987 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में शवों की पहचान नहीं हो पाने के कारण उन्हें जमीन में दफन किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह तक 987 शव बरामद किए गए हैं। सबसे अधिक 321 शव चितवन में मिले हैं, जिनमें विभिन्न मानव अंग भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश शव ऐसी स्थिति में हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। इसके अलावा रसुवा में 27, नुवाकोट में 95, धादिङ में 55, गोरखा में 65, तनहुँ में 38, नवलपरासी पूर्व में 216 और नवलपरासी पश्चिम में 170 शव बरामद किए गए हैं। इनमें से मंगलवार सुबह तक केवल 56 शवों की पहचान हो सकी है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार पहचान नहीं हो पाने वाले 581 शवों को जमीन में दफन किया जा चुका है। चितवन, नवलपरासी, नुवाकोट, कास्की समेत विभिन्न जिलों में दफन किए गए शवों में से 262 शवों के बारे में यह भी पता नहीं चल सका है कि वे महिला के हैं या पुरुष के। बरामद किये गए 121 शव पुरुषों और 198 शव महिलाओं के बताए गए हैं। सबसे अधिक शव चितवन में दफन किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार यहां 280 शवों

को जमीन में दफन किया गया है। चितवन में मिले 321 शवों में से केवल 12 की पहचान हो सकी है और इन सभी को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। चितवन पुलिस ने बताया कि बाकी शवों की पहचान नहीं होने पर उन्हें भी दफन किया जाएगा। इसी तरह नवलपरासी पूर्व में 159 शव और कास्की में 78 शव दफन किए गए हैं। बरामद होने के बाद तत्काल पोखरा ले जाए गए शवों की पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्हें जमीन में दफन किया गया। इसके अलावा कई शव अभी भी विभिन्न अस्पतालों में रखे गए हैं। इन शवों की पहचान करने का प्रयास जारी है। पुलिस ने बताया कि यदि इनकी भी पहचान नहीं हो पाती है, तो उन्हें भी इसी तरह जमीन में दफन किया जाएगा।

नेपाल के त्रिशूली-नारायणी नदी से मिले 321 शव, 280 के फॉरेंसिक परीक्षण और डीएनए की प्रक्रिया शुरू

काठमांडू। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली और नारायणी नदी के तटीय क्षेत्रों से मिले 321 शवों में से अब तक 280 शवों का फॉरेंसिक परीक्षण और डीएनए नमूना संकलन किया जा चुका है। इन शवों को चितवन के देवघाट स्थित प्रबंधन स्थल पर सुरक्षित तरीके से रखा गया है। भरतपुर अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. रामप्रसाद सापकोटा के अनुसार, 26 अगस्त की रात से ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा त्रिशूली नदी से बरामद शवों को अस्पताल लाकर सुरक्षित रखा जा रहा था। 27 अगस्त की सुबह से फॉरेंसिक विशेषज्ञों के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम को तैनात कर शवों की पहचान के लिए आवश्यक फॉरेंसिक जांच, डीएनए सहित जैविक नमूनों का संकलन और रिकॉर्ड रखने का काम शुरू किया गया। जिला पुलिस कार्यालय चितवन के प्रमुख पुलिस अधीक्षक रामेश्वर पौडेल के अनुसार, अब तक त्रिशूली और नारायणी नदियों से 321 शव बरामद किए जा चुके हैं।

इनमें से 12 शवों की पहचान हो चुकी है और उनके परिजनों ने उन्हें ले लिया है। बरामद शवों में 66 महिलाएं, 116 पुरुष, 7 बालक, 6 बालिकाएं तथा 126 ऐसे शव हैं, जिनकी पहचान या स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस

अधीक्षक पौडेल ने बताया कि भविष्य में पहचान सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार देवघाट स्थित प्रबंधन स्थल पर शवों को सुरक्षित तरीके से रखा गया है। भाद्र 13 को 96, भाद्र 14 को 103 और भाद्र 15 को 81 शवों का प्रबंधन किया गया। उन्होंने बताया कि नदी किनारे शवों की तलाश अभी भी प्रतिदिन जारी है। नदी से बरामद शवों को भरतपुर अस्पताल लाकर फॉरेंसिक जांच और डीएनए नमूना संकलन के बाद देवघाट स्थित प्रबंधन स्थल पर सुरक्षित तरीके से रखने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

यूरोजोन में महंगाई बढ़कर 3.3% पर पहुंची, सितंबर 2023 के बाद सबसे ऊंचा स्तर

मॉस्को। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के मंगलवार को जारी शुरुआती अनुमानों के अनुसार, यूरोजोन में सालाना महंगाई दर अगस्त में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गई। जुलाई में यह दर 2.9 प्रतिशत थी। अगस्त का यह स्तर सितंबर 2023 के बाद सबसे अधिक है, जब यूरोजोन में महंगाई दर 4.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त की 3.3 प्रतिशत महंगाई दर 'ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स' के सर्वे में शामिल विश्लेषकों के अनुमान के अनुरूप रही। वहीं, अगस्त 2025 में यूरोजोन की सालाना महंगाई दर 2 प्रतिशत थी। अगस्त में ऊर्जा कीमतों में सालाना बढ़ोतरी जुलाई के 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई। इसे महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजहों में से एक माना जा रहा है। हालांकि, कोर महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई। यूरोजोन में कोर सालाना महंगाई जुलाई के 2.5 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 2.4 प्रतिशत रही।

सेवाओं की कीमतों में सालाना बढ़ोतरी भी जुलाई के 3.3 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई। वहीं, खाद्य पदार्थों, शराब और तंबाकू की कीमतों में बढ़ोतरी 1.2 प्रतिशत पर स्थिर रही। यूरोजोन के विभिन्न देशों में महंगाई दर में काफी अंतर देखने को मिला। सबसे अधिक सालाना महंगाई दर लिथुआनिया में 5.8 प्रतिशत, साइप्रस में 5.2 प्रतिशत, बुल्गारिया में 5.1 प्रतिशत और स्पेन में 3.8 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, सबसे कम महंगाई दर एस्टोनिया में 1.3 प्रतिशत, माल्टा में 1.9 प्रतिशत और फिनलैंड में 2.4 प्रतिशत रही। यूरोस्टैट के अनुसार, यूरोजोन में जुलाई की बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत पर बनी रही। यह जून के संशोधित आंकड़े के बराबर है।

'ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स' के विश्लेषकों को उम्मीद थी कि बेरोजगारी दर जून के शुरुआती अनुमान 6.3 प्रतिशत के स्तर पर बनी रहेगी। हालांकि, संशोधित आंकड़ों के अनुसार जून की बेरोजगारी दर 6.4 प्रतिशत रही थी। उल्लेखनीय है कि यूरोजोन, यूरोपीय संघ के उन सदस्य देशों का एक समूह है जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक और एकमात्र राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया हुआ है। यूरोजोन में वर्तमान में 21 देश शामिल हैं।

एससीओ शिखर सम्मेलन में 28 दस्तावेजों पर मुहर, एआई, ऊर्जा सुरक्षा समेत कई समझौते

बिश्केक। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं ने बिश्केक में आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद मंगलवार को 28 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इनमें मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लेकर ऊर्जा सुरक्षा और पाकिस्तान के शहर लाहौर को एससीओ के पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने से संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। आरआईए नोवोस्ती के संवाददाता ने मंगलवार को बताया कि हस्ताक्षरित दस्तावेजों में एससीओ की 25वीं वर्षगांठ से संबंधित बिश्केक घोषणा पत्र भी शामिल है। इसके अलावा एससीओ के मादक पदार्थ-रोधी केंद्र की कार्यकारी समिति से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दी गई। दस्तावेजों में पाकिस्तान के शहर लाहौर को वर्ष 2026-27 के लिए एससीओ के पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने संबंधी निर्णय भी शामिल है। इसके साथ ही एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की ओर से परमाणु और भौतिक परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने संबंधी घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए।

एससीओ नेताओं ने परिवार संस्था के समर्थन और सुदृढ़ीकरण तथा आपात स्थितियों से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने से संबंधित दो अलग-अलग वक्तव्यों पर भी हस्ताक्षर किए। एससीओ के सदस्य देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को आगे बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई समझौतों को भी अपनाया। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन

में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान समेत दुनिया के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बिश्केक में हुई इस उच्चस्तरीय वार्ता के साथ ही छठे 'वर्ल्ड नोमैड गेम्स' की शुरुआत भी हुई, जिससे यूरेशियाई कूटनीति के लिहाज से यह हफ़्ता काफी व्यस्त रहा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'बिश्केक घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर करना था।

यह दस्तावेज़ संगठन के अस्तित्व के 25 साल पूरे होने और भविष्य की दिशा तय करने वाला था। नेताओं ने संगठन के प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए 2002 के एससीओ घोषणा पत्र में संशोधनों को भी मंजूरी दी। प्रतिनिधि 2030 तक सिंथेटिक ड्रग्स और उनके कच्चे माल के खिलाफ कार्रवाई में तालमेल बिठाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम पर सहमत हुए। शिखर सम्मेलन में 2026 से 2028 के बीच अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार की गई, जो साइबर खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। परमाणु क्षेत्र में, परिषद ने भौतिक परमाणु सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। एजेंडे में सामाजिक और प्रशासनिक मामले भी शामिल थे। सदस्य देशों ने परिवार की संस्था का समर्थन करने और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित देशों की आपसी मदद करने का वादा करते हुए बयान जारी किए। परिषद ने एससीओ के महासचिव और क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट की समीक्षा भी की। साथ ही परिषद के कई पुराने फैसलों को खत्म करने और सद्भावना दूत के खिताब के नियमों में बदलाव को औपचारिक रूप दिया। इस शिखर सम्मेलन के साथ ही ब्लॉक की अध्यक्षता में किर्गिस्तान का अहम दौर पूरा हुआ। अब बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंपी गई है, जो 2027 में राष्ट्राध्यक्षों की अगली काउंसिल बैठक की मेजबानी करेगा।

अमेरिका के आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा इस्तीफा

वाशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका के सेना सचिव (आर्मी सेक्रेटरी) डैन ड्रिस्कॉल ने रक्षा सचिव (डिफेंस सेक्रेटरी) पीट हेगसेथ के साथ कथित तनाव और मतभेदों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया । डैन ड्रिस्कॉल ने लगभग 18 महीने तक पद पर रहने के बाद अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा। उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की कोई ठोस वजह नहीं बताई है।

अमेरिकी रक्षा विभाग और सेना से जुड़ी तकनीकी खबरों को कवर करने वाले समाचार पोर्टल डिफेंस स्कूप और ऑनलाइन समाचार पोर्टल एक्सिओस ने अपनी रिपोर्ट में इस घटनाक्रम की विस्तार से चर्चा की है। डिफेंस स्कूप ने पुष्टि की है कि सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनके इस कदम के बारे में सबसे पहले सोमवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी। एक सैन्य अधिकारी ने कहा, ' सेना सचिव ने राष्ट्रपति से सेना की मौजूदा स्थिति के बारे में बात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया।' इस पर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना की इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है। फॉक्स न्यूज ने सोमवार शाम रिपोर्ट दी कि ट्रंप ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने बयान में कहा, ' सेना सचिव ड्रिस्कॉल ने विभाग में

राष्ट्रपति ट्रंप के 'अमेरिका को फिर से मजबूत बनाने' के एजेंडे को आगे बढ़ाने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने ऐतिहासिक सैन्य अभियानों के दौरान बेहतरीन नेतृत्व प्रदान किया। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में मदद की। इससे अमेरिकी सेना पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई है।

ड्रिस्कॉल का इस्तीफा पीट हेगसेथ के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव की खबरों के बाद आया है। इस तनाव की वजह हेगसेथ का इस साल की शुरुआत में जनरल रैंडी जॉर्ज को आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटाना और अन्य वरिष्ठ कमांडरों को हटाना शामिल है। अगर व्हाइट हाउस ड्रिस्कॉल का इस्तीफा स्वीकार कर लेता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान युद्ध में फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच सेना बिना सीनेट-अनुमोदित नेता के रह जाएगी। इस युद्ध में अमेरिकी सेना तेहरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव में सबसे आगे रही है। माइकल ओबाडल आर्मी के अंडर सेक्रेटरी हैं और अगर ड्रिस्कॉल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वे कार्यवाहक सचिव के तौर पर काम कर सकते हैं। ड्रिस्कॉल अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वह 'ड्रोनबस्टर' हथियार को 'बेहद घटिया' बता चुके हैं। ड्रिस्कॉल येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का करीबी माना जाता है। उन्हें हेगसेथ के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा चुका है। ड्रिस्कॉल, अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र के सेना सचिव हैं। उन्हें 'ट्रम्प 2.0' का एक अहम कमांडर माना गया। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने की बातचीत में कूटनीतिक भूमिका निभाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हेगसेथ और ड्रिस्कॉल के बीच विवाद का एक कारण यह भी रहा कि हेगसेथ ने कथित तौर पर प्रमोशन की लिस्ट से चार अधिकारियों (दो अश्वेत पुरुषों और दो महिलाओं) का नाम हटा दिया था।फरवरी में हेगसेथ ने ड्रिस्कॉल क वरिष्ठ सलाहकार कर्नल डेविड बटलर को हटाने के लिए दबाव डाला था। बटलर ट्रंप के विरोधी जनरल मार्क मिली के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं। ड्रिस्कॉल ने बटलर को नौकरी से निकालने के लिए हेगसेथ के दबाव का विरोध किया था।

नेपाल के बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कार्यदल गठित

काठमांडू। नेपाल के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को सामान्य जनजीवन में वापस लाने के लिए कार्यदल का गठन किया है। मंत्रालय के अनुसार, कार्यदल का गठन 21 दिनों के भीतर प्रारंभिक पुनर्स्थापना और आवश्यक प्रबंधन के काम आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।

कार्यदल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, पेयजल, पुनर्वास, झोलुंगे पुल, मलबा प्रबंधन, संचार और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कार्यों की पहचान, समन्वय और कार्यान्वयन में सहयोग करेगा। इसके साथ ही संबंधित हितधारक संस्थाओं और एजेंसियों को परिचालित कर कार्यों की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग भी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि कार्यदल सभी संबंधित निकायों के बीच आवश्यक समन्वय करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्र पुनर्स्थापना, आवश्यक बुनियादी ढांचे को फिर से संचालित करने और नागरिकों को सामान्य जनजीवन में लौटाने का काम तेजी से आगे बढ़ाएगा।

कार्यदल की प्रमुख जिम्मेदारी

1. आपदा से हुए नुकसान और जोखिम का शीघ्र तकनीकी एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। 2. तत्काल शुरू की जाने वाली आपातकालीन पुनर्स्थापना और आवश्यक सेवाओं की पहचान कर संबंधित निकायों को परिचालित करना।

3. प्रभावित क्षेत्रों, संरचनाओं और परिवारों को जोखिम तथा प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करना।

4. तत्काल, अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्ययोजना तैयार करना।

5. आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री और वित्तीय संसाधनों की जरूरत निर्धारित करना।

6. संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय, सुरक्षा एजेंसियों, निजी क्षेत्र और विकास साझेदारों के बीच समन्वय एवं सहजीकरण करना।

7. पुनर्निर्माण के दौरान भूगर्भीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए Build Back Better के सिद्धांत को लागू करना।

8. आवश्यक नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक और बजट संबंधी निर्णयों के लिए संबंधित निकायों तथा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय को सिफारिश करना।

9. कार्य की प्रगति, सामने आई समस्याओं और उनके समाधान के उपायों सहित नियमित रिपोर्ट पेश करना।

10. कार्यदल के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यों की निगरानी, मूल्यांकन और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

11. आपदा पुनर्स्थापना के दौरान प्राप्त अनुभव और आंकड़ों के आधार पर भविष्य में होने वाली आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव देना।

एक नजर

उदयपुर सिटी-असरवा वंदे भारत अब सूरत तक जाएगी, रेलवे बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी

सूरत,एजेंसी। गुजरात और राजस्थान के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में रेलवे बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है। उदयपुर सिटी-असरवा के बीच चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को सूरत तक विस्तारित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इससे दक्षिण गुजरात के यात्रियों को उदयपुर और राजस्थान के अन्य प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक सीधी रेल सुविधा मिल सकेगी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। सूरत से ट्रेन सुबह 6:10 बजे रवाना होकर दोपहर 1:40 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन उदयपुर सिटी से दोपहर 3:35 बजे रवाना होकर रात 11 बजे सूरत पहुंचेगी। विस्तारित मार्ग में भरूच, वडोदरा, आणंद, मणिनगर, असरवा, हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर और जावर प्रमुख ठहराव होंगे। इस ट्रेन के सूरत तक विस्तार से दक्षिण गुजरात के व्यापारियों, पर्यटकों और राजस्थान जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर उदयपुर और श्रीनाथद्वारा जाने वाले यात्रियों के लिए यह सीधी रेल सेवा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, विस्तारित सेवा किस तारीख से शुरू होगी, इसकी अंतिम आधिकारिक घोषणा पश्चिम रेलवे द्वारा की जानी बाकी है। रेलवे द्वारा परिचालन की तारीख और अंतिम समय-सारिणी जारी किए जाने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। केंद्रीय जल शक्तिमंत्री सी आर पाटिल ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए जल्द ही यह आधुनिक ट्रेन सेवा में प्रारंभ होगी। इसे सूरत सहित दक्षिण गुजरात की महत्वपूर्ण सौगात है।

झामुमो के जनाधार में राजनीतिक पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही कांग्रेसः रघुवर

पूर्वी सिंहभूम। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 'आदिवासी एकता महाजुटान' को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस और आयोजन से जुड़े नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को बयान जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों की मौजूदगी एवं राहुल गांधी का संदेश पढ़े जाने से स्पष्ट है कि यह आयोजन आदिवासी हितों से अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि रैली में सरना आदिवासियों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही और केंद्रीय सरना आदिवासी समिति ने भी आयोजन का विरोध किया था। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पारंपरिक जनाधार में अपनी राजनीतिक पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने परिसीमन को लेकर रैली में किए गए दावों को भी भ्रामक बताया। उनका कहना था कि परिसीमन से संबंधित किसी विधेयक का प्रारूप या प्रस्तावित प्रावधान अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, इसलिए आरक्षित सीटों की संख्या घटने की बात कहना लोगों में भ्रम और भय पैदा करना है। कांग्रेस पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने खरसावां गोलीकांड सहित कांग्रेस के पुराने राजनीतिक इतिहास का उल्लेख किया। आरएसएस को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए दास ने कहा कि झारखंड की पहचान छोटानागपुर की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी है और आरएसएस राष्ट्रसेवा, अनुशासन एवं सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक भूमिका को समझने की सलाह दी और तमाड़ उपचुनाव का हवाला देते हुए सतर्क रहने को कहा। मुस्लिम लीग से कांग्रेस के गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप भी लगाया।

तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद तनाव

हैदराबाद,एजेंसी। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में मंगलवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद तनाव फैल गया, जिसके चलते पुलिस को कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ताओं ने यादाद्री भुवनगिरी विधायक के. अनिल कुमार रेड्डी के कैंप कार्यालय पर कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने फर्नीचर में तोड़फोड़ की और कैंप कार्यालय के बोर्ड पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और स्थानीय विधायक की तस्वीरों पर काला रंग पोत दिया। इसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय पर हमला कर दिया।

उन्होंने कार्यालय पर पथराव किया और कथित तौर पर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। जैसे ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कुछ समय बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सोमवार को हैदराबाद के नामपल्ली स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं द्वारा काला रंग पोते जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक के कैंप कार्यालय पर यह हमला किया था।इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव को नजरबंद कर दिया गया और उन्हें यादाद्री भुवनगिरी जाने व पार्टी नेताओं से मिलने से रोक दिया गया था। जब रामचंद्र राव ने बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने हिरासत

में ले लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए राव ने आरोप लगाया कि तेलंगाना में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राव ने कहा कि एक हफ्ते के भीतर दो बार कांग्रेस सरकार ने मुझे नजरबंद किया है। पहला, प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने से रोकने के लिए और अब, नलगोंडा जिला अध्यक्ष से मिलने से रोकने के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप सोचते हैं कि बार-बार नजरबंद करके मुझे चुप कराया जा सकता है, तो यह आपकी भूल है। आप कभी सफल नहीं हो सकते। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राव से फोन पर बात की और घटनाओं की जानकारी ली। उन्होंने गिरफ्तार किए गए नेताओं का ब्योरा भी मांगा। माना जा रहा है कि उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने को कहा है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंदी संजय कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव को नजरबंद किए जाने की घटना की निंदा की। नेताओं ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की धज्जियां उड़ा रही हैं। विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है।

हरियाणा में चलेगा 'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान'

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित देशव्यापी 'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' के संबंध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया और सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई, 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ यह अभियान 20 फरवरी, 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के समता, ममता, करुणा, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना तथा विभिन्न वर्गों में सामाजिक एकता को और मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से हुआ। नायब सिंह सैनी ने कहा कि समरसता यात्रा आगामी 5 अक्तूबर को हरियाणा में पहुंचेगी और 5 नवंबर, 2026 तक चलेगी। यात्रा के स्वागत के लिए इसके मार्ग में पूरे प्रदेश में प्रवेश द्वार और स्वागत स्थल तैयार किए जाएंगे तथा जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 26 नवंबर, 2026 से 15 जनवरी, 2027 तक छात्रावासों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग केंद्रों में विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का जन्म 649 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा के पावन दिन काशी की पुण्य भूमि पर हुआ था। उनका व्यक्तित्व पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल एवं उज्ज्वल था। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज सुधार का साहसिक और ऐतिहासिक कार्य किया। उस समय जाति-पाति, अंधविश्वास तथा ऊंच-नीच में उलझे समाज में उन्होंने नई जागृति पैदा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ भूमि पर भव्य गुरु रविदास धाम बना रही है। इसका भूमि पूजन 15 मार्च, 2024 को किया गया था। इस परियोजना पर लगभग 124 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परिसर में संत रविदास जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेगमपुरा का अर्थ है ऐसा स्थान, जहां कोई गम नहीं, कोई भय नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई भेदभाव नहीं और कोई शोषण नहीं। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने भी अपनी रचनाओं में गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना है, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और व्यापक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक की

श्रीनगर,एजेंसी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतिक तैयारियों का आकलन किया। बैठक में मुख्य सचिव अटल दुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती, विशेष महानिदेशक समन्वय पीएचक्यू एस.जे.एम. गिलानी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मनदीप के. भंडारी, एडीजीपी, सीआईडी एम.के. सिन्हा, आईजीपी कश्मीर सुजीत कुमार, आईजीपी जम्मू तेजिंदर सिंह, आईजीपी क्राइम ब्रांच सुश्री सारा रिजवी, संभागीय आयुक्त, डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को आतंकी नेटवर्क पर निरंतर दबाव बनाए रखने और जमीनी स्तर पर परिचालन तालमेल बढ़ाने का निर्देश दिया साथ ही उभरते खतरों को निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए आक्रामक क्षेत्रीय वर्चस्व रणनीति अपनाने का आह्वान किया। सुरक्षा तंत्र के लिए जनविश्वास को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने और नागरिकों से बातचीत और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करने का निर्देश दिया।

पुलिस थाना स्तर पर कामकाज की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील शिकायत निवारण की आवश्यकता पर बल दिया और अधिकारियों को पूर्ण व्यावसायिकता के साथ जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के साथ मजबूत और निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रत्येक वास्तविक शिकायत का संवेदनशीलता से समाधान किया जाना चाहिए और प्रत्येक जांच पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को मादक पदार्थों से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अभियान तेज करने और उभरते डिजिटल खतरों की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। साइबर और सोशल मीडिया क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल ने राष्ट्रविरोधी प्रचार, डिजिटल गलत सूचना और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीजीपी और प्रधान गृह सचिव ने उपराज्यपाल को जम्मू-कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया। आईजीपी, डीआईजी और संभागीय आयुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद विरोधी अभियानों, कानून व्यवस्था, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य उभरती चुनौतियों के बारे में उपराज्यपाल को जानकारी दी।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को राजधानी के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने तथा कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोगों पर खड़गे की उत्तराखंड रैली के बाद कार्यक्रम स्थल का कथित तौर पर 'शुद्धिकरण' किए जाने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि कथित घटना सामाजिक भेदभाव और छुआछूत जैसी मानसिकता को दर्शाती है तथा ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड पुलिस ने भाजपा-आरएसएस के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से खड़गे के

कार्यक्रम स्थल के कथित 'शुद्धिकरण' की घटना पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनके अनुसार, इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना न्याय की आवाज को दबाने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति में कथित जातिवादी मानसिकता और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के प्रति भेदभाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यादव ने कहा कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी और सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। देवेंद्र यादव ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान ने दलितों और वंचित वर्गों को समानता, सम्मान और न्याय का अधिकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता कथित 'शुद्धिकरण' प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक अपना विरोध समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर से कांग्रेस डरने वाली नहीं है और पार्टी अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कथित तौर पर सामाजिक अन्याय करने वालों का बचाव कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस सामाजिक समानता और न्याय की बात कर रही है। यादव ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ी है और खड़गे के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता और सुरेंद्र कुमार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विभिन्न जिलों के अध्यक्षों मोहम्मद उस्मान, सिद्धार्थ राव, इंद्रजीत सिंह, हर्ष चौधरी, मंगेश त्यागी, राजकुमार जैन, चौधरी बिजेंद्र कुमार, सुमित शर्मा, महेंद्र भास्कर, महेंद्र मंगला, राहुल ढाका, अमनदीप सिंह सूदन, राजेश यादव और वीरेंद्र शर्मा ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। इसके अलावा प्रदेश महासचिव डॉ. पी.के. मिश्रा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव तरुण कुमार, पूर्व निगम पार्षद अशोक जैन और सोशल मीडिया चेयरमैन राहुल शर्मा सहित विभिन्न विभागों, प्रकोष्ठों और अग्रिम संगठनों के हजारों कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को केवल राजनीतिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान, समानता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय मानती है। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कथित 'शुद्धिकरण' प्रकरण में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुद्दे को लेकर पार्टी अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेगी।

केजरीवाल ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के आरोपियों से हाथ मिलाया, अब न्याय की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं: तरुण चुग

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं गुजरात भाजपा प्रभारी राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने अमृतसर में अपने आवास के बाहर आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन पर कड़ा पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से 1984 के सिख विरोधी नरसंहार को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। तरुण चुग ने कहा कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के उन नेताओं के साथ मंच साझा किया जिन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े गंभीर आरोप और मामले रहे, वही आज भाजपा को उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले यह जवाब देना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा और जिस कांग्रेस पर 1984 के नरसंहार के पीड़ितों को दशकों तक न्याय न दिलाने के आरोप लगते रहे, उसी पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन क्यों किया।

मंगलवार को तरुण चुग बयान ने जारी बयान में कहा कि केजरीवाल 2013 में कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाने के बाद 1984 के मामलों में निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने सवाल किया कि यदि आआपा वास्तव में 1984 के पीड़ितों के प्रति इतनी संवेदनशील थी, तो सत्ता में रहते हुए विशेष जांच और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आज केवल राजनीतिक प्रदर्शन करके पुराने घावों पर राजनीति करना उन

परिवारों के साथ न्याय नहीं है जिन्होंने दशकों तक न्याय की प्रतीक्षा की।

भाजपा नेता ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई भाजपा ने लगातार लड़ी है और भाजपा हर पीड़ित परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है। कांग्रेस शासन के दौरान जिन मामलों में कार्रवाई वर्षों तक लंबित रही, उनमें मोदी सरकार के कार्यकाल में विशेष जांच दल यानी एसआईटी और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता खुला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को कभी वोट की राजनीति के लिए नहीं, बल्कि न्याय के प्रश्न के रूप में उठाया है। तरुण चुग ने कहा कि आज आआपा को यह तय करना होगा कि वह 1984 के पीड़ितों के साथ खड़ी है या कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक रिश्तों को बचाने के लिए उनकी पीड़ा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ केजरीवाल ने राजनीतिक मंच साझा किया, उन्हीं के संदर्भ में आज भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास आआपा की राजनीतिक दोहरेपन को उजागर करता है। चुग ने स्पष्ट कहा कि भाजपा कानून और न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया अदालतों और कानून के माध्यम से आगे बढ़ी है और भाजपा किसी भी मामले में राजनीतिक दबाव के बजाय कानून के अनुसार कार्रवाई का समर्थन करती है। उन्होंने आआपा से कहा कि प्रदर्शन और आरोप लगाने से पहले केजरीवाल को अपने राजनीतिक इतिहास और कांग्रेस के साथ अपने गठजोड़ पर जनता को जवाब देना चाहिए।

वर्तमान पर फोकस करें, निरंतर सीखते रहें और समाज के लिए योगदान दें: राज्यपाल डेका

रायपुर। संत गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, रायपुर में वर्ष 2026-27 में नवप्रवेशित छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम मंगलवार को राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं का राज्यपाल ने सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर परिश्रम करना चाहिए। निरंतर प्रयासों से भविष्य निश्चित रूप से बेहतर बनेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने नवप्रवेशित छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह अध्याय उन्हें केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि एक जागरूक, सशक्त और संवेदनशील नागरिक के रूप में तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में कदम रखते ही छात्राएं उस गौरवशाली परंपरा की उत्तराधिकारी बन गई हैं, जिसने दशकों से बालिकाओं को ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश प्रदान किया है।

डेका ने महिलाओं की तुलना पानी से करते हुए कहा कि जिस प्रकार पानी के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार महिलाओं के बिना समाज भी अधूरा

है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे अपने पास जो कुछ है, उससे संतुष्ट रहें, लेकिन अपने भविष्य को लेकर निरंतर प्रयास करती रहें। राज्यपाल ने कहा कि जीवन सतत सीखने की प्रक्रिया है और हम जीवनभर विद्यार्थी बने रहते हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि आप इंटरनेट युग के विद्यार्थी हैं, तकनीक ने ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, लेकिन तकनीक पर पूर्ण निर्भरता उचित नहीं है। इंटरनेट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन यह मानव बुद्धि और विवेक का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया, बल्कि यह भी विचार करना चाहिए कि हम समाज, अपने पड़ोस और देश की बेहतरी के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसलिए इसे अनावश्यक चिंताओं में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षकों का योगदान अमूल्य है, जिसे पैसों में नहीं मापा जा सकता। शिक्षकों को भी अपने आचरण और व्यवहार से विद्यार्थियों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे वे उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने समाज के लिए छोटे-छोटे सकारात्मक योगदान करें।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)